A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 13 मार्च, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 185, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

दरअसल भारतीय मुसलमानों को उलेमा से आजादी चाहिए

इब्न खलदुन भारती

हम यह सोच रहे थे कि यह तो बहुत पहले खत्म हो चुका है, लेकिन जैसा कि प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट कामू ने अपने उपन्यास 'दि प्लेग' में लिखा है, 'प्लेग का कीड़ा कभी मरता नहीं या हमेशा के लिए लुप्त नहीं होता, वह फर्नीचर में, कपड़ों के संदूकों में वर्षों-वर्षों तक छिपा पड़ा रहता है; वह बेडरूमों, तहख़ानों, संदूकों, और किताबों की आलमारियों में पड़ा अपने दिन काटता रहता है कि शायद वह दिन आएगा जब मनुष्य के विनाश और उसे सबक सिखाने के लिए वह अपने चूहों को फिर से जीवित कर देगा और उन्हें खुशहाल शहर में मरने के लिए भेज देगा।'

सार्वजनिक विमर्श को अस्त-व्यस्त करने वाला फतवा नामक कीड़ा वापस लौट आया है। सेकुलर हुकूमत के दौरान यह फला-फूला, संस्थाओं और व्यक्तियों पर इसने धौंस जमाई, और राजनीतिक व्यवस्था को बंधक बनाया। सरकारें और पार्टियां उसके सामने थर-थर कांपती रहीं, वे इस राक्षस को संतुष्ट करने के लिए अपनी ताकत भर सब कुछ करने की कोशिश करती रहीं, और यह राक्षस उनकी ताकत और साख को अपना निवाला बनाता रहा। फतवे का जमाना लौटता दिख रहा है। दरअसल, यह खत्म नहीं हुआ था, केवल दब गया था, और अब यह फिर से अपना सिर उठा रहा है।

स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी अपने देश भारत के लिए खेल रहे हैं। और यह रमज़ान का महीना चल रहा है, जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं। पाक और जो पूरी तरह पाक नहीं हैं वे मुसलमान भी इस महीने में रोज़ाना रोज़ा रखते हैं, क्योंकि यह उनके समुदाय की एक सबसे पक्की पहचान है। यह रूढ़ियों को लागू करने, व्यक्ति के ऊपर समुदाय के अधिकारों की प्रमुखता स्थापित करने का एक जरिया है। जो रोज़ा नहीं रखता है उसे समुदाय और उसके लोकाचार तथा उसकी पहचान के नजरिए से पक्का गद्दार नहीं, तो एक कलंक, एक विधर्मी, एक पथभ्रष्ट तो जरूर माना जाता है।

इसलिए, चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमी-फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए मोहम्मद शमी ने जब एनर्जी ड्रिंक पीया तो उन्हें 'गुनहगार' और 'मुजरिम' घोषित कर दिया गया। मुस्लिम सोशल मीडिया में तोहमतों का तूफान उठाया गया, और एक मुल्ला ने एक वीडियो में धिक्कार तथा सज़ा के रूढ़िवादी धार्मिक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए इस भावना को आवाज दी।

पवित्रता की इस तरह की पुलिसगिरी की यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक सोच, एक सियासत, एक नजरिए से उपजी व्यवस्था है जिसे आजाद ख्याल, और संप्रदायवाद विरोधी लोगों को अनुशासन में ढालने के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि महिला टेनिस खिलाड़ियों के लिए निर्धारित पोशाक पहनने के लिए टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा की किस तरह निंदा की गई थी। उन्हें स्कर्ट पहनने के लिए पवित्रता के नाम पर शर्मसार किया गया था, क्योंकि स्कर्ट को 'इस्लामी वेशभूषा' की तहजीब के खिलाफ माना गया।

इस विमर्श में इस सभ्य विचार को कोई महत्व नहीं दिया जाता कि धर्म व्यक्ति का एक निजी मामला है। यह मुस्लिम व्यक्ति को मुल्लाओं और समुदाय का बंधक बनाता है और ये दोनों किसी व्यक्ति को 'समुदाय के मानकों' का कथित उल्लंघन करने के नाम पर खरी-खोटी सुना सकते हैं और सजा दे सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, किसी व्यक्ति के आचरण पर फैसला सुनाने और उसे सार्वजनिक तौर पर जलील करने के विशेषाधिकार के इस्तेमाल की यह अकेली घटना नहीं है। हर एक मुसलमान को मजहब की तानाशाही की ओर से सर्वव्यापी निगरानी से आज़ादी चाहिए।

कुरान ने अपने सूरा बकरा (2:184-185) में साफ कहा है कि जो लोग सफर में हैं उन्हें रमज़ान में रोज़ा न रखने की छूट है। उसके मुताबिक शमी वाकई सफर में थे और अपनी पेशेगत ज़िम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन मामला इस तर्क से शांत नहीं होता, क्योंकि इसका ताल्लुक मजहब से कम, और धर्मशास्त्र की सत्ता के वर्चस्व और इससे पैदा होने वा टकराव की विचारधारा से ज्यादा है।

क्रिकेट, भारतीय मुसलमान, और पाकिस्तान- यह एक बेहद जटिल घालमेल है। धार्मिक भावना, राजनीतिक विचारधारा, और खेल का जज्बा, यह सब इसमें बुरी तरह गुंथा हुआ है। फिलहाल हम इस सवाल पर गौर करें कि एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी रमज़ान के दौरान क्यों की? और मुस्लिम अमीरात दुबई इस ट्रॉफी में भारत के सभी मैच अपने यहां करवाने को राजी क्यों हुआ? इन मुल्कों के मुल्लाओं ने और इनके यहां की टेक्नो-इस्लामी सोशल मीडिया ने इस मसले को उस तरह गंभीर नहीं बनाया, जिस तरह 'सेकुलर' भारत में बनाया जा रहा है?

और क्या यह भी कोई आश्चर्य की बात है कि शमी की खाल खींच रहे उन्हीं भारतीय मुसलमानों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि एक इस्लामी मुल्क ने रमज़ान के दौरान अपने यहां उन खेलों का आयोजन क्यों किया, या इन मुल्कों के खिलाड़ियों ने रोज़ा क्यों नहीं रखा? तो फिर, वे इस बात को लेकर इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं कि भारतीय टीम के किसी मुस्लिम खिलाड़ी ने रोज़ा नहीं रखा? क्या इसकी वजह यह है कि वे यह मानते हैं कि एक भारतीय मुसलमान होने के नाते उन्हें अपने मजहबी फर्ज को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य से ऊपर रखना चाहिए था? इस समुदाय के सोच को इस तरह ढाला गया है कि व्यक्ति अपने समुदाय के हितों को देश के हितों से ऊपर रखे और रूढ़ नियम-कायदों तथा सामुदायिक एकता का पालन करे। इन नियम-कायदों का उल्लंघन करने वाले को 'सरकारी मुसलमान' यानी समुदाय का गद्दार कहकर कलंकित किया जाता है।

यह सवाल हैः भारत का मुसलमान पहले एक मुसलमान है या एक भारतीय है? 'हम भारतीय पहले हैं!' कहना उनके सोच में असंभव था, और 'हम मुस्लिम पहले हैं!' कहना राजनीतिक रूप से असुविधाजनक था। इसलिए उन्होंने पहचान की विविधता को लेकर धूर्ततापूर्ण सिद्धांतों का सहारा लिया। लेकिन इस तरह का दोमुंहापन उन्हें यहीं तक ला सकता था। यह मामले को धार्मिक सत्ता के गर्त में ले जा सकता है और भारतीय मुसलमानों को नागरिकता विहीन कर सकता है।

इसलिए जरूरी है कि हम बेलगाम उलेमा को बिना सोचे-समझे फतवों की गोलाबारी करने से रोकने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करें। भारतीय मुसलमान को उलेमा से, धर्मशास्त्र की सत्ता के सूत्रधारों, और राजनीतिक अलगाववाद के उपदेश देने वालों से मुक्ति चाहिए। असली सवाल यह है कि उसे यह मुक्ति दिलाने के लिए क्या सरकार सुधारों के जरूरी कदम उठाएगी?

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

रूप-रंग पर क्या इतराना, छोड़ो यार
बहुत दूर से वापस आना, छोड़ो यार
बंद अंधेरे कमरे में दम घुटता है
दिल क्या है खाली तहख़ाना, छोड़ो यार
वक्त़ ज़रूरत पर हम तुमको देखेंगे
देखेंगे यारी-याराना, छोड़ो यार
भूखे पेट के ख़ातिर गलियों कूचों में
बिखता है इक शख़्स रोज़ाना, छोड़ो यार
तुम्हें यक़ीन के क़ाबिल कोई न समझेगा
इसको उसको राज बताना, छोड़ो यार
शाम ढले सब अपने घर को लौटेंगे
अपना तो बस इक मयख़ाना, छोड़ो यार
भूले-भटके कभी तो कोई सच कह दो
बात बात पर बात बनाना, छोड़ो यार।

- मोहन सगोरिया

वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया बजट

प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं

● केंद्रीय योजनाओं से जोड़ेंगे लाड़ली बहनों को ● एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य ● किसानों को शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा ● हर विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा ● गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया ● सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने पेश किया। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की और कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। यह बजट 4.20 लाख करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि, उनको पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान जरूर हुआ है।

तीथ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये

श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसी प्रकार राम पथ गगन योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गीता भवन में पुस्तकालय, सभागार, साहित्य सामग्री विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व क्षेत्र में 1610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 133 करोड़ रुपए अधिक है।

- **14 स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है-** पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण 507 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल बजट 23535 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 2992 करोड़ रुपए अधिक है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के लिए भी किया जाएगा।
- **आयुष्मान योजना के लिए 2039 करोड़ रुपये-** आयुष्मान योजना के लिए 2039 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। समृद्ध व्यक्ति एवं परिवार के साथ ही समृद्ध गांव की संकल्पना के तहत मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना प्रारंभ की जाएगी। यहां पशुपालन मछली पालन तथा खाद्य संस्करण को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। पंचायत को सर्वांगीण विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं के लिए अनुदान 2507 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 6007 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
- **मनरेगा के लिए 4400 करोड़ रुपये-** प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए 4400 करोड़ मनरेगा के लिए 4050 करोड़ प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के लिए 1000 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना सड़क के लिए 1056 करोड़। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 960 करोड़।
- **सोलर पार्क विकसित किया जाएगा-** वित्तमंत्री ने कहा- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। मुरैना में प्रदेश का प्रथम सोलर पावर स्टोरेज संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत प्रदेश में 2060 आदिवासी बहुल ग्रामों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

शेष पृष्ठ 2 पर...

बजट विश्लेषण

'रेवड़ी' के रेशमी जाल से निकलने की मोहनी पहल

अजय बोकिल

भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट में जहां अधोसरंचना विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा खर्च सरकार की बुनियादी विकास की इच्छाशक्ति दिखती है, वहीं पिछले विस चुनाव में गेम चेंजर बनी लाड़ली लक्ष्मी जैसी रेवड़ी कल्चर योजनाओं से बड़ी खूबसूरती से बाहर निकलने की चाहत भी परिलक्षित होती है। कारण साफ है, राज्यों की आर्थिक सेहत के लिए नकदी बांटने की ये योजनाएं अब नासूर बनने लगी है। यही वजह है कि मप्र सहित अन्य राज्यों में भी लाड़ली बहना, लाड़की बहीण, लाडो बहना जैसी नारी लुभावन योजनाओं से किनारा करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। चुनावी वादों के बाद भी किसी राज्य ने इस राशि में इजाफा नहीं किया है। उल्टे उसकी पात्रता सीमा में कटौतियां जरूर शुरू कर दी है ताकि कम से कम पैसा देना पड़े। वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट में भी यही स्पष्ट संकेत है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लाड़ली बहना योजना का बजट पिछले वर्ष की तुलना में घटा दिया है। हालांकि बहनों को हर माह दिए जाने वाले 1250 रू. की राशि में कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन विस चुनाव में इस राशि को बढ़ाकर 3 हजार रू. करने के वादे से की भी कन्नी काट ली गई है। इसका बड़ा कारण तो सरकारी खजाने पर बढ़ता बोझ है। सरकार तकरीबन हर माह कर्ज लेती जा रही है। बजट की 7 प्रतिशत राशि इन कर्जों के ब्याज भुगतान में ही जाने वाली है। बजट में कहा गया है कि सरकार अब लाड़ली बहना योजना को अटल पेंशन योजना से जोड़ेगी। यह पेंशन योजना दरअसल एक अंशदान योजना है, जिससे हर लाभार्थी को एक निश्चित राशि जमा करनी होगी। कुछ समय तक सरकार भी इसमें अंशदान देगी। उसके बदले में लाभार्थी को कम से कम 1 हजार उससे कुछ अधिक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। यही वजह है कि बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 18 हजार 669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जो पिछले वर्ष के बजट में 18 हजार 984 करोड़ की तुलना में 215 रू. करोड़ कम है। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अब लाड़ली बहना हितग्राहियों को अटल पेंशन योजना के अलावा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अपने एक घंटे 32 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कोई नया कर नहीं लगाया, लेकिन पुराने टैक्सों में राहत भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया से तय किया है। समग्रता में देखें तो मोहन यादव सरकार का यह दूसरा बजट विकासोन्मुखी और रोजगार को बढ़ावा देने वाला है। (शेष पेज-2 पर)

पीएम मोदी को मिला मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

पोर्ट लुईस (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरीशस दौरे का बुधवार को दूसरा दिन है। वे मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस समारोह में शामिल हुए हैं। मॉरीशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आजादी मिली थी। यह राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में गणतंत्र बना। भारतीय मूल के भारतीय मूल के सर शिवसागर रामगुलाम की अगुआई में मॉरीशस को आजादी मिली थी। इस दिन को मॉरीशस राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाता है। आज के समारोह में भारतीय सेना की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी इस समारोह में हिस्सा ले रही है। इस दौरान भारी बारिश भी हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी को मॉरीशस के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया।

● मोदी बोले- मॉरीशस का नया संसद भवन बनाने में मदद करेगा भारत

भारत के अपूर्ण इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक : डॉ. दुबे

विक्रमोत्सव

डॉ. जफर महमूद

उज्जैन से

आज इतिहास के पुनर्लेखन की है आवश्यकता है। भारतीय इतिहास का तथ्यनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। यह बात हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. सीताराम दुबे ने विक्रमोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय इतिहास समागम में कही। इतिहास समागम में ''बृहत्तर भारत में इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व एवं विक्रमादित्य'' विषय पर भारत के विभिन्न अंचलों से पधारे विद्वानों ने अपने शोध-पत्रों का वाचन किया।

डॉ. के.सी. लक्ष्मी देवी(गोवा) ने गोवा स्वतंत्रता संग्राम में मध्य -प्रदेश मालवा और उज्जैन के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका पर शोध-पत्र का वाचन किया। डॉ. अनीता (आगरा) ने साहित्य विशेष कर लोक-गाथाओं में विक्रमादित्य के आदर्श को प्रस्तुत किया। डॉ. नरेंद्र सिंह पंवार ने बृहत्तर भारत में विक्रमादित्य के साहित्यिक साक्ष्य विषय पर अपने विचार रखे । अमेरिका से शोधार्थी श्रेया हरि ऑनलाइन उपस्थित हुई। आपने महाकाल मंदिर की कला एवं स्थापत्य, पूजा शैली तथा परमार शासकों के योगदान पर चर्चा की। गुजरात वड़नगर के डॉ. रमेशचंद्र चतुर्वेदी ने प्राचीन शिक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की। नासिक के डॉ. सुरेश पांडे ने बताया कि विश्व में सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हैं वे

विश्व में प्रथम बार बॉडी लैंग्वेज पर आधारित चित्र हैं। हरिद्वार के डॉ. अजय परमार ने हरिद्वार और गढ़वाल में विक्रमादित्य संबंधित साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए कन्नड़ ग्रंथ राजबलीकथे में निहित विक्रमादित्य सम्बन्धी जानकारी दी।

जलगाँव के प्रो. पी.डी. जगताप ने सत्र की अध्यक्षता की।समागम में माधव महाविद्यालय की इतिहास विभागाअध्यक्ष प्रो अल्पना दुभाषे नेकहा कि हमारी परंपराएं,संस्कृति और क्षेत्रीय इतिहास की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने मौखिक इतिहास को इतिहास की एक प्रमुख देन बताया। इतिहास में लोकगीतों के महत्व को भी प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि विक्रम उत्सव जिस तरह से उज्जयिनी में मनाया जा रहा है, निश्चय ही वह हमारी राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक होगा। इतिहासविद् डॉ अंशु भारद्वाज ने कहा कि लोक संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।धर्म और शास्त्रों के वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। भारतीय रीति रिवाज में वैज्ञानिकता को खोजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य शोधपीठ का स्वरूप निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इतिहास के पुनर्लेखन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। डॉ. जे.सी. उपाध्याय, डॉ. रंजना शर्मा ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। डॉ. धर्मेंद्र जोधा ने पीपीटी के माध्यम से देव तीर्थ देवबल्डा मंदिर समूह के संरक्षण और जिर्णोद्धार के कार्य को प्रस्तुत किया। प्रो. श्याम करोटि ने भारतवर्ष से संबंधित विचारधारा में साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। डॉ. विश्वजीत सिंह परमार ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दसवीं शताब्दी ईस्वी तक के बृहत्तर भारत के विषय में जानकारी प्रदान की। डॉ. जे.सी. उपाध्याय इंदौर ने बृहत्तर भारत और हिंदू संस्कृति के प्रसार विषय पर कहा कि मत्स्य पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण और वायु पुराण के अतिरिक्त लौकिक साहित्य,बृहतकथा, जातक कथा, कौटिल्य अर्थशास्त्र और कौमुदीय महोत्सव इत्यादि ग्रंथों में हमारा इतिहास लिपिबद्ध है। संचालन डॉ. प्रीति पांडे ने किया। आभार डॉ. अंजना सिंह गौर ने माना। तकनीकी सत्र लोक साहित्य के पुरोधा डॉ. पूरण सहगल की अध्यक्षता में हुआ। श्री विजय घाटपांडे, डॉ. सुनीता पंवार, डी.पी. ग्वालपंथी,संदीप घाटपांडे, डॉ अंजना सिंह गौर, डॉ. सुनीता मालवीय,डॉ. आकाश ताहिर ने राजा विक्रमादित्य का ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर शोध-पत्र का वाचन किया। डॉ. रंजना शर्मा ने बृहत्तर भारत पर चर्चा की। डॉ. राकेश ढंढ ने भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए नेपाल में भारतीय परंपरा और विक्रम संवत पर भी प्रकाश डाला। अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए डॉ. पूरण सहगल ने विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को लोक आख्यानों के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रीति पांडे ने तथा आभार डॉ मुकेश कुमार शाह ने माना।

सुबह सवेरे
भोपाल ■ गुरुवार, 13 मार्च 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

पेज 1 का शेष 'रेवड़ी' के रेशमी जाल

सरकार ने 3 लाख रोजगार देने का ऐलान किया है। ये रोजगार नए विकसित हो रहे 39 औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेंगे। अगर इस पर समय सीमा में और ईमानदारी से अमल हुआ तो प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत होगी। इसके अलावा छात्रों के लिए पहले से चल रही लैपटॉप योजना के लिए 220 करोड़ और साइकिल के लिए 215 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।

प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों के पुनरीक्षण का ऐलान कर वित्त मंत्री ने बड़ी राहत दी है। ये बदलाव 13 साल बाद हो रहा है, जिसमें सभी भत्ते 7 वें वेतनमान के आधार पर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल तथा 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे। इसी प्रकार उज्जैन सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने गाय और गोपालक का ध्यान रखा है। सरकार दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देगी। गोशालाओं में गायों के आहार के लिए सहायता प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन की गई है।

खास बात यह है कि सरकार मानती है कि अगर अधोसंरचना विकसित हो जाए तो विकास की गाड़ी खुद ब खुद रफ्तार पकड़ लेती है और यह सोच सही भी है और मप्र जैसे राज्य की पहली जरूरत भी है। लिहाजा बजट की सर्वाधिक 17 फीसदी राशि का अधोसंरचना विकास पर खर्च की जाएगी। इसी तरह मानव विकास सूचकांक के आधारभूत कारक स्वास्थ्य पर 12 और शिक्षा पर 11 प्रतिशत राशि खर्च होगी। इसके अलावा नगरीय व ग्रामीण विकास पर 12 फीसदी और कृषि क्षेत्र पर 9 फीसदी खर्च सरकार के इस संकल्प को दर्शाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2047 के विकसित भारत के संकल्प को विकसित मध्यप्रदेश के रूप में क्रियान्वित करना चाहती है।

हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जीते

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा के नगरीय निकाय चुनाव के रिजल्ट बुधवार को घोषित हुए। भाजपा ने 10 नगर निगम में से 9 में जीत दर्ज की है। कांग्रेस का किसी भी निगम में खाता नहीं खुला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। इसी तरह सिरसा नगर परिषद में भाजपा का चेयरमैन बना। सिरसा से कांग्रेस की कुमारी सैलजा सांसद हैं। मानेसर नगर निगम में निर्दलीय डॉ. इंद्रजीत यादव चुनाव जीतीं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुंदर लाल को हराया।

सीमा पार से फायरिंग एक जवान हुआ घायल

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया। जवान की पहचान मन कुमार बेगा के रूप में हुई है। वह गोरखा रेजीमेंट का है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि बॉर्डर पार से स्नाइपर अटैक हुआ है। एलओसी पर ब्लास्ट भी हुआ, जिसके बाद तीन राउंड फायरिंग हुई। फिलहाल सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 20 दिनों में एलओसी पर फायरिंग की ये पहली घटना है। दरअसल 21 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच फ्लैग मीटिंग हुई थी। यह मीटिंग पुंछ सेक्टर के चाका दा बाग में आयोजित की गई थी। जिसमें दोनों सेनाओं के बड़े अधिकारी शामिल हुए थे।

अब जेलेंस्की 30 दिन के युद्धविराम के लिए तैयार

जेद्दाह (एजेंसी)। यूक्रेन वॉर खत्म करने को लेकर मंगलवार को अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका के 30-दिन का युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने की। यह प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम है। इसे स्वीकार करने के लिए यूक्रेन पूरी तरह तैयार है। अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह रूस को इसके लिए राजी करे। जैसे ही मॉस्को सहमति देगा, युद्धविराम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं, आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण की शुरुआत गीता के इस श्लोक से की...

न त्वहं कामये राज्यं न मोक्षं न स्वर्गं नापुनर्भवम्
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्।।

उन्होंने इसका अर्थ भी बताया-मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए। दुःख में पीड़ित प्राणियों के दुःख दूर करने में सहायक हो सकूं,यही मेरी कामना है।

इसके बाद वित्त मंत्री ने शेर पढ़ा... यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है...। हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं, आंकड़े नहीं, विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। युवा वर्ग और छात्रों की बात की तो एक और श्लोक पढ़ा-विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्।

महिलाओं से जुड़ी योजनाएं बताते हुए वित्त मंत्री ने तीसरा श्लोक पढ़ा... यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

- प्रदेश में 5 साल में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रदेश में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं।
- एक जिला-एक उत्पाद पर फोकस रखा जाएगा।
- सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- 50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी सरकार।
- गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
- बजट में कुल 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
- राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रहना अनुमानित है।
- प्रदेश में 14500 एकड़ भूमि पर 39 नए और क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है इससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।
- प्रदेश में 10000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।
- आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को लगभग 30000 करोड़ रुपए के इनसेंटिव दिए जाना संभावित है।
- इस वर्ष उद्योगों को दिए जाने वाले इनसेंटिव के लिए 3250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- जनजातीय बोल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
- हर विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
- नागरिकों के लिए बीमा समिति का गठन होगा।
- 22 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से 3 लाख रोजगार मिलेंगे।
- 22 नए आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
- धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
- किसानों को शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण प्रारंभ की जा रही है।
- उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।
- जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
- 5 वर्ष में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे।
- इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए रखे गए।
- बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और ना ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया।
- आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
- नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26797 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ों रुपए का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- गोशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन 20 रुपये को दोगुना कर 40 किया जा रहा है।
- गो संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58, 257 करोड़ रुपए का बजट। गत वर्ष से 13409 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान।
- किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय।
- 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्टारों के अनुसार महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- राष्ट्रीय उद्यान तथा बफर क्षेत्र में वन्य जीव वन्य प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर सीमा में फेंसिंग की जाएगी।
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी प्रारंभ। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन होगा उपलब्ध। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है।
- वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन के लिए 15 प्रतिशत तथा गैर परिवहन वाहन के लिए 25 प्रतिशत की छूट दी गई है।
- गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ रुपए का बजट रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 1585 करोड़ रुपए अधिक है।
- जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 जेलों का निर्माण तथा नई बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि की जा रही है। जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।
- पुलिस बल के आधुनिकीरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें पुलिस बल को वाहन सुविधा के साथ तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

ओंकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा

विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ओंकारेश्वर में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 594 करोड़ और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 227 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 1950 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं घाटों और धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई और जीर्णोद्धार किया जाएगा।

नगरीय विकास के लिए 18715 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री ने भाषण में कहा कि नगरीय विकास के लिये वर्ष 2025-26 के लिए 18 हज़ार 715 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2024-25 से लगभग रुपये 2 हज़ार करोड़ अधिक है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण लगभग रुपये 507 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।

संभल की जामा मस्जिद में अब होगी रंगाई-पुताई

● हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फबाहरी दीवारों पर रंग-रोगन करें, ढांचे को नुकसान न हो

प्रयागराज (एजेंसी)। संभल की जामा मस्जिद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई-पुताई की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा- मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में ही रंगाई-पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश सुनाया। 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा था- हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। हिंदू पक्ष रंगाई-पुताई का विरोध कर

रहा था। उनका कहना था- रंगाई-पुताई से मंदिर के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, इसलिए परमीशन न दी जाए। 27 फरवरी को हाईकोर्ट में पहली बार इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें मस्जिद के मुतल्लवी और भारतीय पुरातत्व विभाग को भी शामिल किया था। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि अपनी रिपोर्ट दे।

सीएम नीतिश भांग खाकर विधानसभा में आते हैं

● राबड़ी बोलीं-सदन में महिलाओं को बेइज्जत करते हैं

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 9वें दिन बुधवार को सदन में खूब हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा- सीएम नीतिश कुमार भंगेड़ी हैं, वो विधानसभा में भांग खाकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं।

इससे पहले विधान परिषद में राबड़ी देवी और सीएम नीतिश के बीच बहस हुई है। राबड़ी ने कहा- बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। इस बयान पर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा-एनडीए के राज में कोई काम नहीं हुआ। राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा- जब इनके पति हट गए, तब इन्हें सीएम बनाया गया। नीतिश ने कहा-महिलाओं के लिए पहले कोई काम हुआ था। हमने कितना काम किया है।

लाउडस्पीकर के नियम तोड़ने पर होगी जेल !

महाराष्ट्र में कानून बदलने की तैयारी में देवेंद्र फडणवीस

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं और निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक शोर करते हैं तो धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर लाउडस्पीकर ज्यादा आवाज करते हैं तो उनकी परमीशन

खत्म हो जाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर यह जांच करेंगे कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति है या नहीं। एसआई नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सीएम ने महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर कानून बदलने के भी संकेत दिए। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि अब से लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति केवल अस्थायी रूप से दी जाएगी, किसी खास काम के लिए, न कि स्थायी रूप से। उन्होंने पुलिस को भी इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। फडणवीस विधायक देवयानी फरादे के उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है।

अब नौ सेना को भी मिलेंगे महाबली राफेल

● अप्रैल में 26 विमानों की होगी डील, भारत में लगेगी फैक्ट्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय नौसेना फ्रांस की राफेल से अपने पुराने मिग 29 लड़ाकू विमानों को बदलने की तैयारी में है। नौसेना के लिए भारत 26 नए राफेल विमान खरीदेगा। इस सौदे की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2025 में होने की उम्मीद है जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आएंगे। इस पूरे सौदे की कीमत लगभग 7.6 अरब डॉलर होगी। ये नए राफेल एम विमान व पुराने विमानों की जगह लेंगे। ये पुराने विमान अभी भारतीय नौसेना के 300 स्क्वाड्रन व्हाइट टाइगर्स और 303 स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। नए राफेल जेट आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे। ये विशाल जहाज समुद्र में तैरते हुए हवाई अड्डे की तरह होते हैं। इन 26 राफेल विमानों में से 22 राफेल

एम विमान होंगे। ये खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बाकी के चार विमान राफेल बी ट्रेनर विमान होंगे। ये दो सीट वाले विमान होते हैं, जिनका इस्तेमाल पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। ट्रेनर विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं उड़ सकते। इन नए विमानों की डिलीवरी 2029 में शुरू हो जाएगी। राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन भारत में अपनी एक असेंबली लाइन लगाने पर भी विचार कर रही है। इसका मतलब है कि कुछ राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत समेत कई देशों से राफेल विमानों के बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं। भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत खरीदे जाने वाले 60 फीसदी हथियार भारत में ही बनने चाहिए। भारत के इस नए ऑर्डर को मिलाकर दसॉ एविएशन के पास कुल 256 राफेल विमान बनाने के ऑर्डर हैं। इनमें से 190 विमान दूसरे देशों के लिए और 56 विमान फ्रांसीसी वायु सेना के लिए हैं। दसॉ अभी हर महीने तीन विमान बनाती है। इस हिसाब से सभी ऑर्डर पूरे करने में लगभग 7 साल लग जाएंगे। फरवरी में फ्रांस के रक्षा मंत्री ने 20 से 30 और राफेल विमान खरीदने की योजना की घोषणा की थी। इससे साफ है कि राफेल विमानों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। भारत ने जुलाई 2023 में ही 26 और राफेल विमान खरीदने की योजना बना ली थी।

मैहर में फ्लाईओवर से गिरी कार, 10 लोग घायल

● चार की हालत गंभीर, बच्चे का मुंडन कराने बनारस से आया था परिवार

सतना (नप्र)। मैहर के नादन गांव के पास एनएच-30 पर बुधवार दोपहर 3 बजे एक हादसा हो गया। मैहर से लौट रही यात्रियों से भरी एक कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मुंडन कराने मैहर आया था परिवार

घटना दोपहर करीब 3 बजे की है। कार (P65-BR-5656) में सवार सभी यात्री उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं। वे मां शारदा के दर्शन और 2 वर्षीय बच्चे का मुंडन संस्कार कराने मैहर आए थे। नादन देहात थाना प्रभारी केएन बंजारे के अनुसार, रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रैक्टर को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हादसे में एक 2 साल का बच्चा भी घायल हो गया है।

4 सतना अस्पताल रेफर

घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल अमरपाटन में भर्ती कराया गया। चार लोगों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें सतना रेफर कर दिया गया है। घायलों में 2 साल का बच्चा भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है।

भोपाल में पुलिया किनारे मिला नवजात का शव

● रहवासियों की सूचना पर पहुंची पुलिस, बॉडी को पीएम के लिए भेजा

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एयरपोर्ट रोड दाता कॉलोनी पुलिया किनारे पॉलिथीन में नवजात बालक का शव मिला है। शव को कपड़े में लपेटकर पॉलिथीन में रखा गया था। स्थानीय रहवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंचे डायल 100 स्टॉफ ने बॉडी को कब्जे में लिया। पीएम के लिए बॉडी को हमीदिया अस्पताल की मर्चुरी में रखवा दिया गया है। बच्चा एक से दो दिन पहले ही जन्मा नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि बॉडी पर किसी अस्पताल की सील या चिट नहीं लगी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। जिससे साफ होगा कि बच्चे को किसने फेंका है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही उसकी मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

टायर में आने के बाद शव देखा

नगर निगम के कर्मचारी रामदीन ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिया किनारे सफाई कार्य चल रहा था। नगर निगम की गाड़ी के पहिये के करीब नवजात के शव को देखा। इसके बाद मोहल्ले वालों को मामले की जानकारी दी। मौके पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। तब पुलिस को बुलाया गया।

म.प्र.में सूरज के तीखे तेवर, धार में पारा 39 डिग्री पार

● भोपाल, इंदौर-उज्जैन सबसे ज्यादा गर्म; नर्मदापुरम-जबलपुर संभाग भी तपे

भोपाल (नप्र)। मार्च महीने में सूरज के तेवर तीखे हो रहे हैं। मंगलवार को मध्यप्रदेश के कई शहरों में गर्मी का असर देखा गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे ज्यादा गर्म रहे। जबकि नर्मदापुरम-जबलपुर संभाग में भी पारा बढ़ गया।

ऐसा ही मौसम अब आगे भी बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को इंदौर संभाग का धार शहर सबसे गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 39.1 डिग्री रहा। वहीं, नर्मदापुरम में तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह रतलाम में 38.5 डिग्री, खजुराहो में 38.4 डिग्री, गुना में 38.1 डिग्री, दमोह में 37.5 डिग्री, मंडला, शिवपुरी-सिवनी में 37.2 डिग्री और सागर में पारा 37.1 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि, रात में पारे में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बड़े शहरों में ग्वालियर-उज्जैन सबसे गर्म हैं। यहां तापमान 37.5 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में 37.3 डिग्री और भोपाल में 37.1 डिग्री रहा। जबलपुर में 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

आज से मिल सकती है राहत

उत्तर-पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव होगा। जिसका असर अगले एक-दो दिन में देखने को मिलेगा। जिससे दिन-रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है।

मिथिलेश कुमार बने बीएसएनएल मध्यप्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक

भोपाल। मिथिलेश कुमार ने भारत सरकार की दूरसंचार कम्पनी बीएसएनएल के मध्यप्रदेश दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक के पद पर आज पद

भार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व श्री मिथिलेश कुमार, भोपाल स्थित दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त थे, पदोन्नति पर बीएसएनएल मध्यप्रदेश दूरसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक के पद पर उनकी पदस्थापना हुई है । श्री मिथिलेश कुमार वर्ष 1991 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवाएं (आईटीएस) से हैं तथा उन्होंने संचार से सम्बंधित संस्थापन, विस्तार और मेंटेनेंस के क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं । श्री मिथिलेश कुमार को दूरसंचार क्षेत्र में 34 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है ।

बजट में कर्मचारियों को मिली निराशा

3 प्रतिशत डीए, स्वास्थ्य बीमा योजना पर सरकार के मौन से कर्मचारी नाराज

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट से कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है। सरकार ने जुलाई 2024 से बकाया 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) देने और बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा नहीं की। इससे कर्मचारी नाराज हैं। हालांकि सरकार ने भत्तों को 7वें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित करने की घोषणा की है, पर इससे भी कर्मचारी खुश नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि ये तो पांच साल पहले किया जाना था।

सरकार ने नहीं दिया मांगों पर ध्यान

मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल करने, लंबित डीए देने, स्वास्थ्य बीमा योजना, उच्च पदनाम देने जैसी मांगों को लेकर बजट में घोषणा होती तो कर्मचारियों का हित दिखाई देता। सिर्फ भत्तों के पुनरीक्षण की घोषणा को स्वागत योग्य कहा जा सकता है।

निराशाजनक बजट

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि राज्य सरकार का बजट निराशाजनक है। इसमें कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। स्वागत योग्य सिर्फ पेंशनरों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला है। सरकार को 3 प्रतिशत डीए, स्वास्थ्य बीमा योजना पर बात करनी थी।

घोर निराशाजनक बजट

मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी कहते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। जिन कमेटियों की रिपोर्ट लागू किया जाना था उनके लाभों का भी कोई जिक्र नहीं है। वेतन विसंगतियों से संबंधित मामलों का भी कोई प्रावधान नहीं रखा। कर्मचारियों के लिए बजट घोर निराशाजनक है।

श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करनी थी

सीटू भेल के महासचिव दीपक गुप्ता ने बजट को कर्मचारियों-श्रमिकों के लिए निराशाजनक बताया है। गुप्ता ने कहा कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत ही कम है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आम आदमी को जीवन यापन करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 25000 रुपए प्रतिमाह होना चाहिए। जिस पर सरकार का ध्यान ही नहीं है। राज्य सरकार का बजट तो संतुलित है, पर कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। पुरानी पेंशन, लंबित महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य बीमा योजना, पदोन्नति जैसे मुद्दों को बजट में शामिल नहीं किया गया। बजट में ये भी ध्यान नहीं रखा गया कि राजकोषीय घाटा कैसे कम होगा। योजनाएं घोषणाओं की तरह सिर्फ कागजों तक पहुंच कर न रह जाएं।

एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों के भत्ते बढ़ेंगे

1 अप्रैल से 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेंगे सभी भत्ते ; 13 साल बाद हुआ बदलाव

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश सरकार ने 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान के अनुसार किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते 6वें वेतनमान के अनुसार साल 2010 में तय किए गए थे। इसमें परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपए है, जो वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक हफ्ते के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों में सचिवालय भत्ता, विकलांगता भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता और आदिवासी क्षेत्र भत्ता शामिल हैं। इसके अलावा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, जोखिम भत्ता और पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, सिलाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता दिया जाता है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से महंगाई के अनुरूप भत्तों में वृद्धि की मांग कर रहे थे। हालांकि नए भत्तों के लिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा। पहले वेतनमान लागू होने के 5 साल के भीतर भत्तों में बढ़ोतरी कर दी जाती थी, लेकिन इस बार 7वें वेतनमान के लागू होने के 110 महीने बाद यह निर्णय लिया गया है।

पुनरीक्षण में जल्दी करे सरकार

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार हर बार वेतनमान बढ़ा देती है और भत्तों को भूल जाती है। 6वें वेतनमान तक तो यह भी था कि सरकार 4 से 5 साल में भत्ते बढ़ा देती थी, पर इस बार तो 9 साल 2 महीने बाद सिर्फ घोषणा की है। वे कहते हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू होना है। ऐसे में सरकार 7वें वेतनमान के अनुसार भत्तों का पुनरीक्षण जल्दी करे और 8वें वेतनमान में वेतनमान देने के साथ ही भत्ते भी दे दिए जाएं।

बजट में वृद्ध पेंशनर वर्ग को भूली सरकार-पेंशनरों में भारी आक्रोश

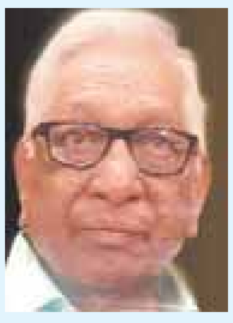

भोपाल। बजट 2025-26 में प्रदेश के वृद्ध पेंशनरों के लिए कोई प्रावधान नहीं कर सरकार ने आसंवेदनशीलता का परिचय दिया है, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बजट को पेंशनर हितों की घोर उपेक्षा वाला बताया। गजट नोटिफिकेशन के बाद भी 18 वर्ष से लंबित छठवें वेतनमान के 32 माह एवं 8 वर्षों से लंबित 27 माह के एरियर्स भुगतान सहित महंगाई राहत का बजट में प्रावधान नहीं कर पेंशनरों के प्रति आसंवेदनशीलता प्रकट की है। जोशी ने आरोप लगाया कि चिकित्सा के अभाव में कोविड के कारण अनेक पेंशनर की मृत्यु का भी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। बजट में गंभीर बीमारी से ग्रस्त पेंशनर्स के उपचार का भी कोई प्रावधान नहीं किया पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा का प्रावधान नहीं कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। आमोद सक्सेना ने आरोप लगाया की पेंशन नियम-1976 में संशोधन को विगत कई वर्षों से लंबित कर पेंशनर की मृत्यु के बाद उसकी अभावग्रस्त अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा परित्क्ता पुत्री को केंद्र सरकार के समान परिवार पेंशन का बजट में प्रावधान नहीं कर सरकार ने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी नीति प्रदर्शित की है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बजट को घोर निराशाजनक बताते हुए पेंशनरों को अपनी मांगों के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहने का आवाह्न किया है।

बजट पर किसने क्या कहा

नगरों के सुनियोजित विकास के लिये वचनबद्ध है राज्य सरकार : मंत्री विजयवर्गीय

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्तुत किये गये बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के नगरों के सुनियोजित विकास के लिये वचनबद्ध है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि सिंहस्थ-2028 को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जायेगा। विभाग के बजट में सिंहस्थ की तैयारी के लिये 2 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विभागीय बजट की राशि को बढ़ाते हुए बजट में वर्ष 2025-26 के लिये 18 हजार 715 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्र के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई सेवाएँ प्राथमिकता एवं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराई जायेगी।

समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करने वाला जनकल्याणकारी बजट : मंत्री चौहान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता किसान भाई और नारी शक्ति पर केंद्रित है। बजट में समाज के सभी वर्गों के समग्र कल्याण के लिए प्रावधान किए गये है। उन्होंने कहा कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जल जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए है। मंत्री श्री चौहान ने समावेशी और जनहितकारी बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव और उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा का आभार व्यक्त किया है।

राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बजट : राज्य मंत्री अहिरवार

भोपाल। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट सर्व-समावेशी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार हुआ यह बजट प्रधानमंत्री श्री मोदी के समग्र विकास के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उत्थान के दर्शन पर आधारित है। इससे राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि बजट में वन और पर्यावरण संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। राज्य में वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिये पर्याप्त दर राशि आवंटित की गई है, जिससे वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलेगी।

प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है बजट : ऊर्जा मंत्री तोमर

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया गया। बजट प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाये गये इस बजट में ग़रीब ,युवाओं, अन्नदाता और नारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऊर्जा विभाग के लिए इस वर्ष 37 हजार 734 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 10 हजार 343 करोड़ रूपये अधिक है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। मंत्री श्री तोमर ने बताया कि अटल गृह ज्योति योजना के लिए 7132 करोड़ रूपये और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13909 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आर.डी.एस.एस. योजना के लिए 2894 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 774 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 5 एच.पी. पंपों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क बिजली देने के लिए 5299 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है । उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत वितरण कंपनियों के सतत् लोन अंशपूंजी में परिवर्तित किए जाने हेतु राशि 5000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सर्वांगीण विकास के साथ श्रीकृष्ण और श्रीराम की आस्था का बजट : मंत्री शुक्ला

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया गया बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गरीब युवा, अन्नदाता और नारी (जीवायएएन) पर ध्यान के मंत्र पर फोकस के साथ ही धर्म और अध्यात्म की धरोहर को संरक्षित करने वाला है। मंत्री श्री शुक्ला ने बजट में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7132 करोड़ रुपए एवं कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ रुपए का प्रावाधान किये जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से किसान और आम नागरिक अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनेंगे। परिणामस्वरूप वर्ष 2047 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के लक्ष्य की प्राप्ति में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा। मंत्री श्री शुक्ला ने कहा कि बजट में श्रीकृष्ण पाथेय योजना के साथ श्री राम पथ गमन योजना के लिए भी समुचित राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सर्व-सुविधायुक्त वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में गीता भवन बनाए जाने के मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्णय का भी स्वागत किया है।

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला सर्वहितैषी-सर्वकल्याणकारी बजट : मंत्री सारंग

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश बजट 2025-26 की सराहना करते हुए इसे 'विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला सर्व हितैषी व सर्वकल्याणकारी बजट' बताया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'ज्ञान पर ध्यान के मंत्र' को इस बजट में पूरी तरह आत्मसात किया गया है। मंत्री श्री सारंग ने बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व और वित्त मंत्री श्री देवड़ा द्वारा प्रस्तुत 4,21,032 करोड़ रूपये के ऐतिहासिक बजट ने प्रदेश में विकास, समृद्धि और जनकल्याण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह बजट आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मध्यप्रदेश के विकास को समर्पित सर्वसमावेशी दूरदर्शी बजट : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत 2025-26 का बजट सर्वसमावेशी और दूरदर्शी है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन

जैसे सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर कुल 23 हज़ार 535 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 2,992 करोड़ रूपये अधिक है। यह स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तृत और सुदृढ़ बनाने में सहयोगी होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सर्व-हितकारी और विकासोन्मुखी बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री (वित्त) श्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं उप मुख्यमंत्री (वित्त) श्री देवड़ा के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का एक प्रभावी दस्तावेज है। यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और अधोसंरचना विकास को भी समान रूप से प्राथमिकता दी है। प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्प और कला-संस्कृति को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएँ शुरू की जा रही हैं।

उमंग सिंघार ने बजट को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा- सरकार कर्ज लेकर कर्ज पटाने में लगी है

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए आज कहा कि ये सिर्फ जादुई आंकड़ों का और जुमलेबाजी का बजट है। इस बजट में प्रदेश के सभी वर्गों के लिए प्रावधान नहीं है और अगर कुछ है भी तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सिंघार ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कर्ज का बजट है। इससे किसी के घर का विकास नहीं होता। आज हर व्यक्ति पर 50 हजार से ज्यादा का कर्ज सरकार ने लाद दिया है। सरकार कर्ज लेकर कर्ज पटाने में लगी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रदेश की जनता को आसमान दिखा दिया, सपने दिखा दिए, लेकिन ये सपने कब पूरे होंगे। इसका कोई स्पष्ट जवाब सरकार के पास नहीं है।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के बजट में आदिवासी समुदाय के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 100 आदिवासी गांवों को सौर ऊर्जा देंगे। क्या सिर्फ 100 ही गांव सरकार को दिखाई दे रहे हैं बाकी का क्या होगा? इस बजट में युवाओं की नौकरी और एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर कोई योजना नहीं है। इसके अलावा नई भर्तियों को लेकर भी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि राम पथगमन के लिए सिर्फ 30 करोड़ दे रहे हैं इससे क्या होगा? भाजपा राम के नाम पर वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उनके पथ के लिए कुछ नहीं करना चाहती। सरकार कह रही है प्रदेश के अंदर भुखमरी नहीं है जबकि हकीकत ये है कि बीमारू राज्यों की सूची में मध्यप्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पर है। फिर भी झूठे आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं।

संपादकीय

अपने ही गड्ढे में गिरता पाकिस्तान

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोमवार को कथित आतंकी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने जिस शातिर अंदाज में एक समूची ट्रेन को अगवा कर 450 यात्रियों को बंधक बनाया, पाक सेना के कई अफसर और जवानों को मारा, उससे यही साबित हो रहा है कि पाक ने भारत के लिए आतंकवाद का जो गड्ढा खोदा था अब वो खुद उसी में गिर रहा है। ये पंक्तियां लिखे जाने तक पाक सेना और बीएलए के लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी थी और सभी बंधकों को छुड़ाने में सफलता नहीं मिली थी। पाक सेना के मुताबिक ट्रेन में बैठे आतंकी आत्मघाती जैकेट बैठे हुए हैं और बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तरीका भी हमास द्वारा इजराइल पर किए हमले के बाद बंधकों को शील्ड बनाकर ब्लैकमेल करने जैसा है। लेकिन बीएलए ने जिस तरह एक ट्रेन को अगवा किया और लोगों को बंधक बनाया, वह समूची दुनिया के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि विश्व भर में सक्रिय अन्य आतंकी और अलगाववादी दल भी ऐसा कर सकते हैं। पाक सेना का दावा है कि उसने 24 से जारी लड़ाई में 27 लड़ाकों को मार गिराया है। कुल 214 बंधकों में से 155 को छुड़ा लिया गया है, जबकि 59 अभी भी लड़ाकों के कब्जे में हैं। गौरतलब है कि बीएलए ने सोमवार दोपहर को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को सुरंग के पास अगवा कर लिया था। हालांकि बीएलए का दावा है कि उसने बच्चों और महिलाओं को छोड़ दिया था। पाकिस्तान सरकार इसे आतंकी घटना बताकर इसे सख्ती से कुचलने की बात कर रही है। जबकि बलूच लड़ाकों द्वारा जारी एक आडियो टैप के अनुसार उनका कहना है कि यह इंसाफ और जिंदा रहने की लड़ाई है। हम ट्रेन हाईजैक के इस ऑपरेशन में शामिल हुए हैं क्योंकि यह हमारे हक की लड़ाई है। अपहरणकर्ताओं के अनुसार वो बलूच लोगों से कहना चाहते हैं कि वह इस संघर्ष में शामिल हो और इसका हिस्सा बने। हम ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। आज हमने इस ट्रेन को हाईजैक किया। हमारे साथ आपके लिए और इस जमीन के लिए अपना खून बहा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल यह इलाका पाक के दक्षिण-पश्चिम में है, जिसके क्षेत्रफल में ईरान और अफगानिस्तान की भी जमीनें शामिल हैं। यह 347190 वर्ग किमी में फैला है। इस जमीन के नीचे मौजूद तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम और अन्य खनिजों का अकूत भंडार है। इससे यह पाक का सबसे अमीर राज्य भी है। इसके बावजूद यह इलाका पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। पाकिस्तान ये बेशकीमती खदानें चीन को देकर अपनी किस्मत चमकाना चाहता है। उस पर 124.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का 42 प्रतिशत है। बलूचिस्तान की यह घटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वहां पाक सरकार और सेना की अत्याचारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस हद तक जा पहुंचा है। बलूचों का आरोप है कि एक तो 1947 में उन्हें जबरन पाकिस्तान में शामिल कर उनकी स्वायत्तता छीन ली गई, दूसरे बलूचिस्तान के नैसर्गिक संसाधनों का पाक हुक्मरानों ने भरपूर शोषण किया। पाक हुकूमत की नीयत पर बलूचियों को भरोसा नहीं रहा है। वो अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। लेकिन पाक सेना जबरन उनकी आवाज दबा रही है। इसके लिए सभी क्रूर और हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाक सरकार इसे आतंकवादी तरीका बताती है, जो पाक को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है। लेकिन पाक को अब समझ आ रहा है कि आतंक को बढ़ावा देने का अंजाम क्या होता है, लेकिन क्या वो इससे कोई सबक लेगा?

नजरिया

अशोक भाटिया

लेखक मुंबई निवासी टिप्पणीकार हैं।

क्या बलूचिस्तान आजादी के नजदीक है?

ट्रेन हाईजैक करते हुए बलूच आर्मी ने पाकिस्तान के 11 सैनिकों को मार दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस ट्रेन में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक दल के अफसर व आईएसआई के अधिकारी भी बैठे हैं। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में बैठे पाकिस्तान के अधिकारियों की संख्या 182 से ज्यादा है। ये सभी अफसर छुट्टी मनाने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जा रहे थे। बलूचों ने ट्रेन में बैठे इन पाकिस्तानी अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि जरा सी हरकत की तो सभी यात्रियों को मार दिया जाएगा। खबर सामने आ रही है कि बलूच आर्मी ने इस ट्रेन से महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायिन आर्मी और मजीद ब्रिगेड इस मिशन को लीड कर रही है।

बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी द्वारा क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की 11 मार्च की घटना ने, बलूच और पाकिस्तानी शासन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों की यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। बीएलए लड़ाकों द्वारा किया गया ये अटैक और हाईजैक बलूचों की स्वतंत्रता की लगातार मांग का नतीजा है। यह लड़ाई आर्थिक उत्पीड़न, राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने, सांस्कृतिक भेदभाव और स्टेट स्पॉन्सर्ड दमन के आरोपों का भी अंजाम है, जो 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद से ही चल रहा है।

बताया जाता है कि हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान अपनी आजादी के बेहद नजदीक पहुंच गया है। अब तो अमेरिका तक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। इस ट्रेन में पाकिस्तान के 450 लोगों को बंधक बना लिया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान की सेना ने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की तो सभी यात्रियों को मार दिया जाएगा। बलूचिस्तान के कच्छी जिले के माच टाउन के आब-ए-गम इलाके के पास ट्रेन को हाईजैक किया गया है। खबर के मुताबिक, करीब छह हथियारबंद लोगों ने ट्रेन पर गोलीबारी की, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार, बीएलए का मुकाबला करने के लिए पाक सेना एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रही है और एयर एसेट तैनात किए गए हैं। ट्रेन हाईजैक करते हुए बलूच आर्मी ने पाकिस्तान के 11 सैनिकों को मार दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस ट्रेन में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक दल के अफसर व आईएसआई के अधिकारी भी बैठे हैं। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में बैठे पाकिस्तान के अधिकारियों की संख्या 182 से ज्यादा है। ये सभी अफसर छुट्टी मनाने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जा रहे थे। बलूचों ने ट्रेन में बैठे इन पाकिस्तानी अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि जरा सी हरकत की तो सभी यात्रियों को मार दिया जाएगा। खबर सामने आ रही है कि बलूच आर्मी ने इस ट्रेन से महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायिन आर्मी और मजीद ब्रिगेड इस मिशन को लीड कर रही है।

गौर करने वाली बात ये है कि कुछ दिन पहले ही बलूच आर्मी ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान पर अपने हमले के तरीकों को बदल देगा। कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के पांच संगठनों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हाथ मिला लिया था। इनमें तीन संगठन बलूचिस्तान के हैं और दो संगठन सिंध प्रांत के हैं। मकसद साफ है बलूचिस्तान और सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग करना और काम शुरू भी हो चुका है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की संसद में भी बयान दिया गया था कि बलूचिस्तान से पांच से सात प्रांत खुद को आजाद घोषित करने वाले हैं।

बलूचिस्तान में पिछले एक साल में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है। नवंबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 26 लोग मारे गए थे और 62 अन्य घायल हुए थे। तेल और खनिज संपन्न बलूचिस्तान, पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसक अलगाववाद से जूझ रहा है। बलूच विद्रोही समूह अक्सर सुरक्षा कर्मियों, सरकारी परियोजनाओं और क्षेत्र में 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजनाओं को निशाना बनाकर हमले करते रहते हैं।

गौरतलब है कि भारत में इससे पहले अगस्त, 2016 में बलूचिस्तान का मुद्दा जोरदार ढंग से चर्चा में आया था और तब इसकी वजह यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से दिए अपने भाषण में बलूच लोगों पर पाकिस्तान के अत्याचारों का जिक्र किया था। तब प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी जबकि बलूचिस्तान के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया था।

ज्ञात हो कि इस समय पाकिस्तान में क्षेत्रफल के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है लेकिन यहां आबादी कम है और बाकी प्रांतों के मुकाबले यहां के लोग गरीब हैं। यहां रोजगार के मौके भी बहुत कम हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधन विशेषकर तेल यहां बहुत ज्यादा है और इसलिए यह सूबा पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है।

बलूचिस्तान के इतिहास के अनुसार 1947 में भारत के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना तभी से बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और हुकूमत के द्वारा की जा रही हिंसा, कत्लेआम और उनकी आवाज को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों को देखा है। 1947 से पहले बलूचिस्तान में मकरान, लस बेला, खारन और कलात इलाकों के सरदार शामिल थे। ये सभी ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार थे। इन सभी में कलात का सरदार सबसे शक्तिशाली था और बाकी इलाकों के सरदार उसके अधीन थे।जब भारत से ब्रिटिश शासन का अंत होने वाला था तब कलात के अंतिम 'खान' सरदार अहमद यार खान ने एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र की मांग को उठाया। अहमद यार खान ऐसा मानते थे कि उनके और मोहम्मद अली जिन्ना के संबंध बेहद अच्छे हैं और इस वजह से उन्हें पाकिस्तान में शामिल करने के बजाए एक अलग देश की मान्यता मिलेगी। 1947 में पाकिस्तान ने उनके साथ एक मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि अंग्रेज चाहते थे कि कलात का पाकिस्तान में विलय हो जाए।अक्टूबर, 1947 में पाकिस्तान ने एक चतुराई भरा खेल खेला और कलात का पाकिस्तान में विलय करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। 17 मार्च, 1948 को पाकिस्तान की सरकार ने कलात के तीन इलाकों को अपने साथ शामिल कर लिया। इसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर यह अफवाह फैल गई थी कि कलात के खान भारत में विलय करना चाहते हैं। इस वजह से 26 मार्च, 1948 को पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में घुस गई और इसके अगले दिन कलात के विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। लेकिन इस विलय के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

बलूचिस्तान की आजादी के लिए अब तक पांच युद्ध (1948, 1958-59, 1962-63, 1973-1977 और 2003 से जारी) लड़े गए हैं, जिनमें से पहला युद्ध 1948 में शुरू हो गया था। पाकिस्तान की सेना के लिए बलूच विद्रोहियों से निपटना बेहद मुश्किल साबित हुआ है। पाकिस्तान की सेना और वहां की हुकूमत ने बलूच विद्रोहियों का निर्दयता से दमन किया है, इस तरह के आरोप अलग बलूचिस्तान की मांग करने वाले लोगों की तरफ से लगातार लगाए जाते हैं। पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान के लोगों का अपहरण करने, उन पर अत्याचार करने, मनमानी गिरफ्तारी करने और हत्याओं तक को अंजाम देने के आरोप लगते रहे हैं। इस बारे में कोई सटीक आंकड़ा नहीं है कि 1948 से अब तक पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के कितने नागरिकों को मारा है। लेकिन एनजीए के मुताबिक, 2001 और 2017 के बीच लगभग 5,228 बलूच नागरिक लापता हो गए और यह मान लिया गया है कि वे अब जिंदा नहीं हैं।इसी कारण पाकिस्तान की सेना की हिंसा के जवाब में बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे संगठनों ने भी हिंसा का सहारा लिया है। उन पर ऐसा आरोप लगता है कि उन्होंने गैर-बलूच लोगों की हत्याएं की हैं और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। इस्लामाबाद के एनजीओ की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'बलूच विद्रोही गुटों, मुख्य रूप से बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने 2023 में बलूचिस्तान में 78 हमले किए, जिसमें 86 लोग मारे गए और 137 लोग घायल हुए। ये हमले मुख्य रूप से बलूचिस्तान के मध्य, दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों के 19 जिलों में हुए और इनमें बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया।'

एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि बलूचिस्तान की अलग मांग को किस वजह से समर्थन मिला। इसके पीछे दो बातें सामने आती हैं। पहला भेदभाव होना। बलूचिस्तान के लोगों का इतिहास, भाषा और संस्कृति एक जैसी है लेकिन यह बात कही जाती है कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही वहां सिर्फ पंजाब के लोगों का दबदबा है। पंजाब के लोगों का पाकिस्तान की नौकरशाही, सारे संस्थानों पर जबरदस्त कब्जा रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी पंजाबियों का दबदबा है और इस वजह से बलूचिस्तान के लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। दूसरी वजह है कि बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि उनके संसाधनों पर कब्जा हो रहा है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। बलूचिस्तान का इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और यह ईरान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित है और इसलिए भी यह पाकिस्तान के लिए रणनीतिक लिहाज से अहम है लेकिन पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तुलना में यहां के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस वजह से बलूचिस्तान के लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि पाकिस्तान में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और उन्हें अलग देश दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। उनका तर्क है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादातर फायदा पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे चीन के द्वारा बनाए जा रहे ग्वादर पार्ट में अरबों रुपए का निवेश हुआ है लेकिन इससे बलूचिस्तान को फायदा नहीं मिला है बल्कि पंजाबी और सिंधी इंजीनियरों को यहां काम पर रखा गया। इस वजह से कई बार बलूच लड़ाकों ने पंजाब के लोगों को निशाना बनाया है।अब लगता है कि बलूची आर पार की लड़ाई के मूड में है और वह अलग बलूचिस्तान लेकर ही मानेंगे।

दृष्टिकोण

लोकेन्द्र सिंह

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

'भारत' ही लिखें और बोलें

देश के प्राचीन एवं संविधान सम्मत नाम 'भारत' का जिस प्रकार विरोध किया जा रहा है, उससे दो बातें सिद्ध हो जाती हैं। पहली, देश में अभी भी एक वर्ग ऐसा है, जो मानसिक रूप से औपनिवेशिक गुलामी का शिकार है। भारत के 'स्व' और उसकी सांस्कृतिक परंपरा को लेकर उसके मन में गौरव की कोई अनुभूति नहीं है। दूसरी, वास्तव में यह समूह 'भारत विरोधी' है। भारतीयता का प्रश्न जब भी आता है, तब यह समूह उसके विरुद्ध ही खड़ा मिलता है। एक तरह से यह उसका स्वभाव बन गया है। देश की जनता देखकर आश्चर्यचकित है कि 'भारत' का विरोध करने के लिए कांग्रेस सहित उसके समर्थक राजनीतिक दल एवं वैचारिक समूह कित स्तर पर पहुँच गए हैं। 'भारत' को 'भारत' कहने पर आखिर हाय-तौबा क्यों मची हुई है? भारत विरोधी समूह को एक बार संविधान सभा की बहस पढ़नी चाहिए। निश्चित ही उसे ध्यान आएगा कि तत्कालीन कांग्रेसी नेता अपने देश का नाम 'भारत' ही रखना चाहते थे लेकिन अंग्रेजी मानसिकता के दास लोगों के सामने उनकी चली नहीं। आखिरकार 'भारत' के साथ 'इंडिया' नाम भी चिपक गया।

कांग्रेस के वरिष्ठ एवं सम्मानित नेता सेठ गोविंद दास ने कहा था कि वेदों, महाभारत, पुराणों और चीनी यात्री ह्वेन-सांग के लेखों में 'भारत' देश का मूल नाम था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में 'इंडिया' को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तव में भारत हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन इंडिया शब्द के साथ ऐसी कोई गौरव की अनुभूति कराने वाली बात नहीं जुड़ी है। भारत कहने पर, हमें समृद्धशाली परंपरा का स्मरण होता है। स्वाभाविक ही हम लोग अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं। जब भी किसी ने अपने देश को भावनात्मक आधार पर स्मरण किया है, उसने उसके लिए भारत शब्द ही उपयोग किया है। राष्ट्रगान में 'इंडिया भाग्य विधाता' नहीं आता, अपितु 'भारत भाग्य विधाता' गाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 'भारत माता कौन है' व्याख्यायित किया, इंडिया माता नहीं? स्वतंत्रता के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों ने भी 'भारत माता की जय' का नारा बुलंद किया। संविधान सभा में जब भारत के नाम को लेकर आए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तब प्रसिद्ध गांधीवादी नेता एवं कांग्रेस सरकार के मंत्री महावीर त्यागी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की दलीलों पर व्यंग्य करते हुए कहा कि 'यह (नेहरूजी) हैरो (विलायत) में पढ़े हैं और मैंने केवल एक छोटी-सी पाठशाला में अंग्रेजी पढ़ी है। पर मेरे गुरु नंदराम जी ने छठी क्लास में मुझे बताया था कि व्याकरण के अनुसार 'प्रोपर नाउन' (व्यक्ति वाचक संज्ञा) का अनुवाद नहीं होता है, पर जब हैरो की ग्रामर के विद्यार्थी कहते हैं कि नामों का अनुवाद भी हो सकता है, तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ। पर मेरे प्रतिष्ठित मित्र को सचेत रहना चाहिए कि कल के अंग्रेजी समाचारपत्रों में यह छप सकता है कि ऑनरेबिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर 'जैमरैड कैनालू' के कहने पर त्यागी ने अपना संशोधन वापस लिया'। नेहरूजी ने जब पूछा कि क्या कहा तुमने? तब वाकपटुता के लिए प्रसिद्ध महावीर त्यागी ने कहा- जैम का अर्थ है जवाहर, रैड का लाल और कैनालू का अर्थ है नेहरू। दरअसल, महावीर त्यागी ने 'इंडिया दैट इज भारत' प्रस्ताव में एक ऐसी गलती की ओर ध्यान आकर्षित किया था, यदि उसे नहीं सुधारा जाता तो आज संविधान की दुहाई देने वाले लोग कहते हैं कि अपने देश का नाम न तो इंडिया है और न ही भारत, संविधान के अनुच्छेद-1 के अनुसार हमारे देश का नाम 'इंडिया दैड इज भारत' है। महावीर त्यागी का आधा संशोधन मानकर 'इंडिया दैट इज भारत' से उद्धरण चिह्न हटा लिए और इंडिया शब्द के बाद कौमा लगा दिया।

कांग्रेस के वरिष्ठ एवं सम्मानित नेता सेठ गोविंद दास ने कहा था कि वेदों, महाभारत, पुराणों और चीनी यात्री ह्वेन-सांग के लेखों में 'भारत' देश का मूल नाम था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में 'इंडिया' को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। वास्तव में भारत हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन इंडिया शब्द के साथ ऐसी कोई गौरव की अनुभूति कराने वाली बात नहीं जुड़ी है। भारत कहने पर, हमें समृद्धशाली परंपरा का स्मरण होता है। स्वाभाविक ही हम लोग अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं। जब भी किसी ने अपने देश को भावनात्मक आधार पर स्मरण किया है, उसने उसके लिए भारत शब्द ही उपयोग किया है। राष्ट्रगान में 'इंडिया भाग्य विधाता' नहीं आता, अपितु 'भारत भाग्य विधाता' गाया जाता है।

बहरहाल, विश्व में शायद ही किसी देश का ऐसा उदाहरण नहीं मिले, जिसका उसकी अपनी भाषा में नाम अलग हो और अंग्रेजी में अलग। सबका एक ही नाम चलता है। दुनियाभर में अनेक उदाहरण हैं, जब देशों ने बाह्य पहचान को हटाकर अपने 'स्व' का धारण किया और अपना वास्तविक नाम स्वीकार किया है। इनमें हमारे ही पड़ोसी देश म्यांमार और श्रीलंका उदाहरण हैं। भारत में अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया कि उसका नाम अब केवल 'भारत' लिखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस सहित उसके समर्थित समूह में हलचल मच गई है। अभी कोई नहीं जानता कि संसद के विशेष सत्र में ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा या नहीं। यदि आए तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और इस दिशा में कोई प्रस्ताव नहीं भी आता तब एक संकल्प सबको लेना चाहिए कि जहाँ तक संभव होगा, हम अपने देश का नाम भारत ही लिखें और बोलें।नोएडा में 10 मार्च, 2025 को 'विमर्श भारत का' पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि 'भारत को अंग्रेजी नाम इंडिया नहीं बल्कि 'भारत' कहा जाना चाहिए। यह 'कंस्टीटूशन ऑफ इंडिया' है, 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' है...ऐसा क्यों है? ऐसा सवाल उठना चाहिए। इसे सुधारा जाना चाहिए। अगर देश का नाम भारत है, तो इसे इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। भारत एक भौगोलिक इकाई या संवैधानिक ढांचे से कहीं अधिक है; यह एक गहन दर्शन और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है'। स्मरण हो कि इससे पहले 2 सितंबर, 2023 को सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी भी यह आग्रह कर चुके हैं कि भारत को भारत ही कहना चाहिए। उन्होंने सकल जैन समाज के एक कार्यक्रम के दौरान उचित ही कहा कि 'हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल शुरू करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी यही समझाना होगा'। प्रकांड विद्वान स्वर्गीय राजीव दीक्षित से लेकर सदुरु जग्गी वासुदेव तक अनेक महानुभाव यह आग्रह कर चुके हैं कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। कांग्रेस में भी जो राष्ट्रभक्त नेता हैं, उनका आग्रह भी भारत नाम के लिए रहा है।

अभी हाल के वर्षों में यानी 2012 में ही कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि संविधान के अनुच्छेद-1 में और संविधान में जहाँ-जहाँ इंडिया शब्द आया का उपयोग हुआ हो, उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। कांग्रेस के सांसद नाइक ने यह भी कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत से ऐसा नहीं है। परंतु आज एक ऐसे नेता के प्रति स्वामी भक्ति प्रकट करने के चक्कर में कांग्रेसी 'भारत' का विरोध कर रहे हैं, जो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानता है। वह चुनौती भी देते हैं कि संविधान में कहीं भी भारत को राष्ट्र नहीं लिखा है, जबकि संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को एक संप्रभु राष्ट्र कहा गया है। बहरहाल, देश के नाम शुद्धि के लिए संविधान संशोधन हो या नहीं, हमें संकल्प करना चाहिए कि हम अपने लिखने, पढ़ने और बोलने में 'भारत' ही उपयोग करेंगे। यदि ऐसा किया, तब किसी प्रकार के संशोधन की अपेक्षा भी नहीं रह जाएगी। वैसे भी अभी सामान्यतौर पर हम अपने देश के लिए 'भारत' नाम का ही उपयोग करते हैं।

त्यौहारों पर लगते प्रश्न मिटाने का दायित्व किसका?

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखिका स्तंभकार हैं।

होली मात्र रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि भावनाओं का भी त्यौहार है। इस दिन हर रंग अपनी अमिट छाप छोड़ने का प्रयास करता है। पर आजकल यह प्रश्न विचारणीय है कि क्यों हमारे त्यौहार अपना वर्चस्व खोते जा रहे है। क्यों एक बेहद खूबसूरत त्यौहार को छपरी जैसे शब्दों से सम्बोधन किया जाता है और कुछ तुच्छ लोग इसका समर्थन भी कर देते है। यह हमारे लिए इसलिए भी विचारणीय है कि, जो त्यौहार स्वयं में रंगों को समेटे हुए सबके जीवन में रंग भरता है, वही कुछ लोगों के लिए त्रास का कारण कैसे बन जाता है। इसका जवाब है कि हर युग के बहुत कम युवा अपनी संस्कृति को गम्भीरता से लेते है।

भारतीय त्यौहार अपने आप में विभिन्न रंगों को समेटे हुए है। बात अगर रंगों से भरे त्यौहारों की हो तो होली का नाम आते ही हर रंग का चित्र हमारे सामने आ जाता है।इस दिन हम अपने आपको न सिर्फ रंगों से रंगा पाते है , कई बार तो इन रंगों में हमारे गिले-शिकवे भी धुल जाते है। भारतीय त्यौहारों की यह अपनेआप में प्रशंसा है कि बिना किसी को नुकसान पहुचाएं, हम खुशियों को मनाते है।

ऐसा ही एक प्रयास हमें इस बार की होली में करना चाहिए, जिससे की होली मात्र त्यौहार बनकर नहीं बल्कि संदेशात्मक त्यौहार बनकर समाज के सामने आए। जिस प्रकार होलिका दहन से हम बुराई का नाश और सच्चाई की जीत को नमन करते हुए मनाते है, ठीक उसी प्रकार अपने अतीत की कुछ कडवी यादों को जलाकर नवजीवन की शुरुआत कर सकते है। हम दूसरों के जीवन में क्या सुखद दे सकते है। इस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। जिस प्रकार हर रंग अपने भीतर एक नया अर्थ समाए हुए है। उसी प्रकार हमारे भीतर के भाव भी हमेशा अर्थपूर्ण जीवन की तलाश में रहते है। बीएस हमें उन्हें एक सही दिशा देने का प्रयास करते रहना चाहिए।

होली मात्र रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि भावनाओं का भी त्यौहार है। इस दिन हर रंग अपनी अमिट छाप छोड़ने का प्रयास करता है । पर आजकल यह प्रश्न विचारणीय है कि क्यों हमारे त्यौहार अपना वर्चस्व खोते जा रहे है। क्यों एक बेहद खूबसूरत त्यौहार को छपरी जैसे शब्दों से सम्बोधन किया जाता है और कुछ तुच्छ लोग इसका समर्थन भी कर देते है। यह हमारे लिए इसलिए भी विचारणीय है कि ,जो त्यौहार स्वयं में रंगों को समेटे हुए सबके जीवन में रंग भरता है , वही कुछ लोगों के लिए त्रास का कारण कैसे बन जाता है। इसका जवाब है कि हर युग के बहुत कम युवा अपनी संस्कृति को गम्भीरता से लेते है। होली का त्यौहार ऐसे ही एक बनावटी आवरण से ढक चुका है, जहां इस त्यौहार का अर्थ मात्र लोगों को रंगों से , या कई बार कीचड़ से रंगना और स्त्रियों के साथ अभद्रता करना ही होता है । जबकि होली किसी भी प्रकार की उद्दंडता का नहीं बल्कि सोहार्द्र का त्यौहार है। जब हम रंगों से रंग जाते है, तब हर तरह की असमानता खत्म हो जाती है। न कोई ऊँचा होता है और न ही कोई नीचा , सब समान हो जाते है। इस त्यौहार का असली उद्देश्य नफरत को मिटा कर प्रेम को स्थापित करना है। बुराई को खत्म करके अच्छाई को हमारे जीवन में लाने का नाम होली है। जिस प्रकार हर युग एक क्रान्ति का युग होता है। उसी प्रकार हर त्यौहार भी कुछ नया करने और बीते भ्रामक प्रचार को मिटा कर उस त्यौहार की सार्थकता को समाज के सामने लाने का समय होता है।यह हमारा दायित्व बनता है कि अपने आचरण द्वारा हम अपने त्यौहार के महत्व को बताएं न कि उनपर प्रश्नचिह्न लगाने का कार्य करें। और इसकी जितनी ज़िम्मेदारी हमारे युवाओं पर है, उतनी ही ज़िम्मेदारी हमारी भावी पीढ़ी की भी है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए की हमें अपनी खुशियों को मनाने के लिए किसी को मिटाना नहीं बल्कि मिलाना पड़ता है।

हमारे त्यौहार धरोहर है उन पूर्वजों की जो एक सुखद, सफल और मानवता का संदेश देकर हमारे कंधों पर एक भारी दायित्व छोड़कर गए है, जिसमें हम इस त्यौहार को मानवता और अपनेपन के रंगों से भी मनाए। जिससे हम समाज को जागरूक और मजबूत बनाने में सहयोग कर सकें।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

वक्रोक्ति

श्याम बोहरे

लेखक स्तंभकार हैं।

स्वागत करो, जीवन की जरूरतों के पूरा होने की इच्छा मत करो

जब मेरे मन में जनता जनार्दन रहती है, तो फिर जनता रोजगार, सड़क, कुंआ और पुलिया निर्माण, अस्पताल, स्कूल की अपेक्षा क्यों करती है? यह शिकायत है लोकतंत्र में लोक के सेवक (मंत्री जी) की। लोक सेवक जब कभी जहां भी पधारें उनके दर्शन और वचनामृत पाने के लिए भीड़ बनकर अपने सेवक का पुष्पहार से स्वागत करके जनता (मालिक) अपने जीवन को कृतार्थ करे, यही जनता का परम कर्तव्य है। गीता में कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जिसका मतलब है कि अपने सेवक के स्वागत के लिए भीड़ बनो, पुष्प वर्षा करो लेकिन जीवन की बुनियादी जरूरतों की इच्छा मत करो।

फागुन आया तो लगे बोराने। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, एकदम बकवास। हम कोई देवतुल्य, नान-बायोलॉजिकल महामानव तो हैं नहीं, जो बकवास कर सकें। आपको मालूम होना चाहिए कि हेकड़ी दिखाना, दम्भ, अकड़, क्रोध, बकवास आदि पर लोक सेवक (मंत्री जी) का अधिकार है। यह 'सदगुण' केवल उन्हें ही शोभा देते हैं। क्या हो गया जो यह भूमिका बनायी जा रही है? खास कुछ नहीं। हमारे लोक सेवक जनता को दर्शन लाभ कराने और उसका कल्याण करने के लिए पधारे थे। परम्परा के अनुसार जनता जनार्दन (मालिक) ने भीड़ बनकर स्वागत किया, पुष्पहार पहनाये। लेकिन नासमझी में मालिक ने अपनी तकलीफें राहत पाने की उम्मीद में लिखा हुआ आवेदन लोक सेवक को सौंपा। बस फिर क्या था, सेवक जी भड़क गये मालिक पर। पिला दिये वचनामृत, कहा तुम्हें भीख मांगने की आदत पड़ गई है। 'लेने की नहीं, देने की आदत बनाओ'। तो इसमें गलत क्या है? सही गलत कुछ भी समझो, बड़े-बड़े नेता इस तरह की बातें करते रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जान एफ केनेडी ने कहा था कि, ''यह मत पूछो कि अमेरिका ने तुम्हें क्या दिया, यह पूछो कि अमेरिका को तुमने क्या दिया।'' उस समय दुनिया भर में इस बात के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी की बहुत तारीफ होती थी। उस समय यही बात बड़े-बड़े लोग कहने लगे। उनकी बहुत तारीफ होने लगी, तालियां पिटती थीं, अखबार वाले इसे प्रमुखता से छापने लगे। जब यही अच्छी बात हमारे महान लोक सेवक ने की तो बवाल मच गया, आखिर क्यों? 'टीटई चली हंस की चाल, टूटे हाड़ निकल गये प्राण'। मतलब जब महान लोगों की बातें गैर-महान लोग करने लगते हैं, तो लोग असल और नकल में भेद समझते हैं।

इस मामले में दो बातें समझने कोशिश करते हैं। पहली तो यह कि जनता जिन कामों को कराने की गुहार मंत्री जी से करती है, उनमें से अधिकांश काम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को करना होते हैं, मंत्रियों को नहीं। अधिकारी और कर्मचारी अपने काम समय पर करते नहीं तो उन कामों के लिए आवेदन मंत्री के पास आते हैं। मंत्री ये आवेदन उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के पास भेज देते हैं, जिन्होंने ये काम नहीं किये थे। जिन मामलों में मंत्री गम्भीर होते हैं, विशेष जोर देते हैं वे कुछ काम हो जाते हैं। जाहिर है कम ही काम हो पाते हैं, अधिकांश नहीं। इसलिए भी आवेदनों का ढेर बार-बार लगता रहता है।

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की कुरई जनपद की प्रेमपुरा ग्राम पंचायत में लोगों ने एक आवेदन देते हुए कहा कि, ''इतनी दरख्वास्तें (आवेदन) दीं कि एक मैयत फुंक जाती (अर्थी जल जाती)। इस तरह आवेदनों का अम्बार लगना अधिकारियों, कर्मचारियों की नाकामी का नमूना है। मंत्री का काम अधिकारियों पर लगाम कसना है। यदि मंत्री अधिकारियों से काम नहीं करा पाते तो यह मंत्री की नाकामी है। लोकतंत्र का तकाजा है कि यदि काम नहीं करा सकते तो जाइये, छोड़िये कुर्सी ही तो है, अर्थी तो नहीं जो उठ ही न सके। दूसरी बात को इस तरह समझते हैं। हमारे घरेलू सेवक झाड़ू-पोंछा करने, खाना बनाने, कपड़े साफ करने, बगीच सम्हालने सरीखे और भी काम करने वाले, हमसे कहें कि ये सब काम इस तरह करेंगे कि आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। आप संतुष्ट रहे और खुश रहें तभी हमें वेतन दीजिए। इसके लिए हमें अस्सी हजार रूपए प्रतिमाह दीजिए, रहने के लिए मकान और काम पर आने के लिए वाहन सुविधा दीजिए। जाहिर है हम कहेंगे कि इतने महंगे सेवक रचाने की हमारी हैसियत नहीं है। हम आपको नहीं रख पायेंगे।

लोकतंत्र में जनता के टैक्स के पैसों से मंत्रियों और अधिकारियों को भारी भरकम वेतन-भत्ते, रहने के लिए बड़े आलीशान बंगले, काम पर आने के लिए कारें और घरेलू काम करने के लिए अनेकों काम करने वाले सहित कई तरह की सुविधायें मिलती हैं। इतना अधिक पाने वाले जनता का काम संतोष जनक ढंग से नहीं कर पाते, तो जनता ऐसे सेवकों को क्यों रखे। जनता यह क्यों नहीं कहती कि इतने महंगे सेवक रखने की हमारी हैसियत नहीं है।

आधुनिक रोबोटिक

कर्मयोगी
(वरिष्ठ पत्रकार और लेखक)

टेली सर्जरी से दूरियां मिटाकर जीवन बांटती रोबोटिक्स

एसएस इनोवेशन ने दूसरे ग्लोबल एसएमआरएससी 2025 के माध्यम से भारत की पहली मोबाइल टेली-सर्जिकल यूनिट मंत्रा-एम का लोकार्पण करके एक प्रेरक पहल की है। यह आधुनिक मोबाइल सर्जिकल यूनिट दूरदराज के इलाकों के लिए आधुनिक रोबोटिक-असिस्टेंट सर्जरी तथा रियल-टाईम टेली सर्जरी क्षमता के साथ उच्च गुणवत्ता की सर्जिकल देखभाल को सुलभ बनाएगी।

दुनिया में बदलते वक्त के साथ आधुनिक चिकित्सा ने नए आयाम स्थापित किए हैं। जिसने जीवन प्रत्याशा में आशातीत वृद्धि की है। आधुनिक तकनीक ने भौगोलिक बाधाओं को दूर करके चिकित्सा विशेषज्ञता को दूर-दराज के इलाकों में पहुंचाने में मदद की है। चिकित्सकीय विशेषज्ञता और तकनीकी प्रगति के साम्य ने मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आधुनिक चिकित्सा को रोबोटिक्स की बदलावकारी क्षमता ने समृद्ध किया है। सर्जरी के क्षेत्र में निरंतर आधुनिक बदलाव आ रहे हैं, ऐसे में इनोवेशन, विश्वस्तरीय साझेदारियों तथा चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाता है। इसी दिशा में एसएस इनोवेशन ने दूसरे ग्लोबल एसएमआरएससी 2025 के माध्यम से भारत की पहली मोबाइल टेली-सर्जिकल यूनिट मंत्रा-एम का लोकार्पण करके एक प्रेरक पहल की है। यह आधुनिक मोबाइल सर्जिकल यूनिट दूरदराज के इलाकों के लिए आधुनिक रोबोटिक-असिस्टेड सर्जरी तथा रियल-टाईम टेली सर्जरी क्षमता के साथ उच्च गुणवत्ता की सर्जिकल देखभाल को सुलभ बनाएगी।

हाल ही में संपन्न एसएमआरएससी 2025 में उद्योग जगत के गणमान्य दिग्गज एकजुट हुए। इनमें शामिल थे अंतर्राष्ट्रीय थ्योरी सिस्ट एवं फ्यूचरिस्ट डाफ मिचियो काकू; इनोवेटर एवं शिक्षा सुधारक श्री सोनम वांगचुक, सर्जिकल रोबोटिक्स के जनक डॉ फ्रेडरिक मोल। इन सभी दिग्गजों ने रोबोटिक सर्जरी और हेल्थकेयर के भविष्य को आयाम देने में इनोवेशन की भूमिका पर रोशनी डाली। कई महाद्वीपों से 150 से अधिक अग्रणी विशेषज्ञों सहित 1200 से अधिक डॉक्टरों ने रोबोटिक सर्जरी के भविष्य और आधुनिक प्रगति पर मंथन किया। चिकित्सकीय विशेषज्ञता और तकनीकी प्रगति के बीच के अंतर को दूर कर इस सम्मेलन ने आधुनिक चिकित्सा में रोबोटिक्स की बदलावकारी क्षमता को दर्शाया। सर्जरी के क्षेत्र में निरंतर आधुनिक बदलाव आ रहे हैं। ऐसे में यह सम्मेलन आधुनिक इनोवेशन, विश्वस्तरीय साझेदारियों तथा चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण के महत्व को दर्शाता है।एसएस इनोवेशन्स के मुख्यालय से 1700 किलोमीटर की अधिक दूरी पर बैंगलोर के एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल में टेलीसर्जरी को अंजाम दिया गया, जो रिमोट सर्जिकल केयर में बड़ी उपलब्धि है।

निस्संदेह, यह पहल भारत में रोबोटिक सर्जरी और टेलीमेडिसिन में नया बदलाव लेकर आएगी। आधुनिक मोबाइल टेली-सर्जिकल यूनिट चिकित्सा तकनीक के आधुनिकीकरण, चिकिसा सेवाओं की बुनियादी सुविधाओं को नया आयाम देने और आधुनिक सर्जिकल देखभाल की पहुंच बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सर्जिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने तथा रोबोटिक सर्जरी एवं हेल्थ टेक इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ने में भारत की स्थिति को मजबूत बनाएगी। वास्तव में टेलीसर्जरी की आधुनिक क्षमता दूरदराज के वंचित क्षेत्रों में विश्वस्तरीय रोबोटिक-असिस्टेंट प्रक्रियाओं को सुलभ बनाकर सर्जिकल केयर की सभी बाधाओं को दूर कर रही है। टेली सिंक मोबाइल यूनिट में सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और आधुनिक सर्जिकल रोबोटिक्स शामिल हैं। जो रिमोट एवं ऑन-साईट सर्जिकल टीम के बीच रियल टाईम सहयोग को सुनिश्चित करता है। इस इनोवेशन के ज़रिए सर्जन न्यूनतम लेटेंसी के साथ प्रक्रिया को पूरा कर सकता है, इस तरह आधुनिक सर्जिकल केयर पहले से कहीं अधिक सुलभ हो जाती है।

एसएस इनोवेशन्स संस्थाप व चेयरमैन डॉ सुधीर श्रीवास्तव, कहते हैं, एसएसआई मंत्रा-एम एक मोबाइल टेलीसर्जिकल यूनिट विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक बदलाव लाने का एक आंदोलन है। हाई-स्पीड टेलीकम्युनिकेशन एवं सैटेलाईट कनेक्टिविटी के साथ यह भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है तथा उन वंचित समुदायों के लिए जीवन रक्षक रोबोटिक-असिस्टेट सर्जरी को सुलभ बनाता है, जो इससे वंचित हैं। निरंतर अनुसंधान एवं इनोवेशन के ज़रिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि आधुनिक रोबोटिक सर्जरी उन सभी लोगों की पहुंच में आ जाए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस दौरान रोबोटिक, यूरोलोजी, जनरल सर्जरी, गायनेकोलोजी, ओंकोलोजी, हैड एंड नैक और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी पर फोकस करते हुए रोबोटिक सर्जरी एवं टेलीसर्जरी में इनोवेशन्स पर चर्चा को बढ़ावा दिया गया। साथ ही एसएस इनोवेशन्स के आधुनिक सर्जिकल केयर में बदलाव रहे प्रमुख सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा 3 की आधुनिक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। देश भर के 70 से अधिक अस्पतालों में इंस्टॉल्ड एसएसआई मंत्रा जटिल कार्डियक प्रक्रियाओं सहित 3000 से अधिक मल्टी-स्पेशलटी सर्जरियों को सुगम बना चुका है।

एसएमआरएससी 2025 में दुनिया भर से ऐसे दिग्गज शामिल हुए जो हेल्थकेयर एवं टेक्नोलॉजी के भविष्य को नया आयाम दे रहे हैं। जाने माने थ्योरिटिकल फिज़िसिस्ट एवं फ्युचुरिस्ट डॉ मिचियो काकु बताते हैं कि एआई, क्वांटम कम्प्युटिंग और रोबोटिक्स की प्रगति ने सर्जरी को नया आयाम दिया है। जिसने प्रेसीज़न मेडिसिन एवं रियल टाइम रिमोट प्रक्रिया को वास्तविकता बना दिया है। निस्संदेह, सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम आने वाले भविष्य को नया आयाम देगा। जो सर्जरी में क्वांटम मैकेनिक्स का इंटीग्रेशन को दर्शाता है। यह सिर्फ रोबोटिक सर्जरी नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिकल रोबोटिक सर्जरी की दिशा में एक कदम है, एक विकास जो चिकित्सा में क्रान्ति ला सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स और रोबोटिक सर्जरी एक साथ मिलकर चिकित्सा जगत में नई खोज का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

सर्जिकल रोबोटिक्स के जनक डॉ फ्रेडरिक मोल मानते हैं कि रचनात्मकता, दृढ़ता के चलते ही हम इस मुक़ाम तक पहुंचे हैं। रोबोटिक्स लगातार विकसित हो रही है और अधिक इंटेलीजेन्ट बन रही है। ऐसे में हम क्षमता के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां मरीज़ और मानवता दोनों का कल्याण सुनिश्चित होगा। इस मौके पर लाइव टेलीसर्जरी और टेली-प्रॉक्टरिंग सेशन के जरिये कार्डियक एवं मल्टीस्पेशलटी क्षेत्रों में रियल टाइम रोबोटिक सर्जरियों का प्रसारण किया गया। यह सुखद है कि 'मेड इन इंडिया' दृष्टिकोण के साथ रोबोटिक सर्जरी में इनोवेशन का कार्य आधुनिक विश्व स्तरीय तकनीकों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। निस्संदेह, रोबोटिक्स हमारा भविष्य है। ऐसे में ये तकनीकें हेल्थकेयर में सटीकता, दक्षता और सुलभता को नई परिभाषा दे रही हैं। भोगोलिक सीमाओं के अंतर को दूर कर और चिकित्सा पेशेवरों को बेजोड़ क्षमता के साथ सशक्त बनाकर लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। निस्संदेह, सर्जिकल उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करके विश्वस्तरीय स्वास्थ्यसेवाएं दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए।

साहित्य महाकुंभ

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
लेखक भारत के राष्ट्रपति के ओएसडी रह चुके हैं। आप पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में चेयर प्रोफेसर हैं।

एक बेहतरीन भारत गढ़ने की दिशा में ठोस कदम साहित्योत्सव

भारत साहित्य सृजन का अद्भुत देश है। विश्व में प्रसिद्ध भारतीय क्लासिक की अपनी अनुगूँज है। कालजयी कृतियों के अलावा दूसरे जो साहित्य सृजन हुए वे भी लोकप्रिय हुए। यह सच हक़ कि भारत में अन्य उत्सवों की भांति रचनाधर्मिता के भी उत्सव साहित्य अकादमी व भारत सरकार के अन्य सम्मानित संस्थानों द्वारा आयोजित होते रहते हैं। इसी कड़ी में देश की राजधानी नई दिल्ली में साहित्य अकादेमी का साहित्योत्सव अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ऐसा दावा किया गया है कि यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य-महोत्सव है। अभी भारत में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हुआ था जिसमें भारतीय अध्यात्म व आस्थाशील लोग आए। यहां करोड़ों भारतीय माँ गंगा में डुबकी लगाई। अब एशिया का साहित्य महाकुंभ 7 से 12 मार्च तक दिल्ली में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया गया। इसमें ज्ञान व प्रज्ञाशील लोग भारतीय साहित्य सर्जना की नदियों में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कहते हैं गंगा आदि नदियां मोक्ष प्रदान करती हैं लेकिन इस भारतीय भूमि पर आयोजित साहित्य महाकुंभ में एकत्रित जन ज्ञान व चिंतन, भारतीय दर्शन व सृजन में डुबकी लगाकर तात्विक-शक्ति प्राप्त कर पाए।

इस महा-आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक भाषा-बोलियों में लिखने-पढ़ने, सोचने-विचारने वाले 700 से अधिक सर्जक, लेखक इसमें शामिल हुए। विश्व के उत्कृष्ट साहित्य सर्जक अच्छे राज्य की परिभाषा इस प्रकार भी करते रहे हैं कि जो राज्य अपने साहित्यकारों, कलाकारों, चिंतकों, भाष्यकारों एवं दार्शनिकों का आदर करते हैं, वे कल्याणकारी राज्य होने का शीघ्र सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के ऐसे आयोजन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारत अपने विरासत में प्राप्त साहित्य, चिंतन, सृजन व नवाचार को सुरक्षित, संवर्धित व प्रोत्साहित करने में रुचि लेता है। नि:संदेह इस महाकुंभ की संकल्पना, आयोजना और उद्देश्य का अभिवादन व अभिनंदन किया जाना चाहिए। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत व साहित्य अकादमी के सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव दोनों बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसे मूर्त रूप प्रदान किया है।

डॉ. के. श्रीनिवास राव ने जब से साहित्य अकादमी में बतौर सचिव कार्यभार ग्रहण किया है ऐसे आयोजनों की श्रृंखला बढ़ी है। साहित्य अकादमी के इस सहियोत्सव की भी आयोजना, संकल्पना के पीछे भी डॉ. राव की अपनी इच्छाशक्ति व सक्रियता दिखती है तभी देश के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार दिल्ली कूच करके इस महाकुंभ में आए। हर राज्यों का प्रतिनिधित्व हुआ। हर बोली-भाषा के लोगों का संगम हुआ। पुराने चावल भी इस साहित्योत्सव में आए तो नवधा लेखक, साहित्य प्रेमी ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति अंकित की।

बहुधा यह देखा गया है कि साहित्य व पुस्तकों से दूरी की बात की जा रही है। इंटरनेट, मोबाइल और एआई के युग में चुनौती भी पढ़ने की संस्कृति के समक्ष दस्तक दी है। पढ़ने की शैली नई पीढ़ी में बदलती जा रही है। साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय के इस आयोजन ने सिद्ध किया है कि साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं जब तक इस देश में रहेंगी, न पढ़ने की संस्कृति खत्म होगी और न ही पुस्तकों के प्रकाशन रुकेंगे। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को सीखने, संवाद करने का भी यह मंच बन पड़ा है क्योंकि इसमें देश की हर विधा के प्रतिष्ठित साहित्यकार अपने चिंतन व परिमार्जित साहित्यिक सिद्धियों को अभिव्यक्त करेंगे। यह प्राचीन काल में किसी बौद्ध संगीति के समतुल्य आयोजन कहा जाए तो कोई अतिश्योक्तिपूर्ण बात नहीं होगी।

देश में हो रहे परिवर्तन को समझते हुए उस अनुरूप साहित्य सृजन करने, साहित्य को गतिशीलता प्रदान करने, नवाचार करने, अभिव्यक्ति की नई उड़ान भरने, देश को गतिशीलता देने व प्रकृति व वसुधा की अच्छाई के साथ जुड़ने हेतु ऐसे सदप्रयास किया जाना चाहिए। यदि मैं इस आयोजन को खुद के साथ जोड़ूँ तो मुझे कहने में यह जरा भी गुरेज नहीं कि यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मेरे विश्वविद्यालय में देश की राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है और मैं साहित्य व सर्जना से इतना जुड़ाव महसूस करता हूँ कि उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अपेक्षा मैं इस साहित्योत्सव में बतौर आमंत्रित लेखक सम्मिलित हुआ। मुझे दर्शक दीर्घा में दीक्षांत समारोह में घिसीपिटी बातें सुनने की जगह साहित्योत्सव में कुछ नया सीखना अधिक पसंद है। यह शक्ति साहित्योत्सव में ही है जो किसी लेखक के लिए अहम हो जाता है। मेरे जैसे साहित्य में अभिरुचि रखने वाले देश के साहित्यकारों में मुझे ऐसी ही अभिप्रेरणा का आभास होता है। यह आयोजन इस प्रकार यदि खिंचाव रखता है तभी इसकी अपनी अहमियत भी है।

भारत में साहित्य को नए प्रकार से देखने, समझने, सृजन करने का यह सबसे उपयुक्त समय है जब विभिन्न विचारधाराओं, भाषाओं, अभिव्यंजनाओं में एकात्मकता सी देखी जा रही है। पूरे देश में लेखन शैली की धार पूरी धारा ही परिवर्तित करने की कोशिश में हैं और नए तरह की साहित्य संवेदना अपना पांव पसार रही है। ऐसे समय में साहित्यकारों का यह महाकुंभ नि:संदेह भारत की नई पीढ़ी में नई लौ प्रज्ज्वलित करेगी और भारत में बदलाव भी आने वाले समय में दिखेगा। वास्तव में साहित्य में ही वह शक्ति होती है जो अपने तरह के देश, काल, वातावरण और मानस सृजित कर नए कलेवर में सोचने समझने की क्षमता पैदा करती है। अब एक बार पुनः भारतीय कालजयी कृतियों को आज़ का लेखक बहुत गहराई से समझने की कोशिश में लग गया है। इस आयोजन से क्या कुछ निकल कर आएगा, यह तो वक़्त तय करेगा लेकिन एक बात तय है कि भारतीय नई पीढ़ी व साहित्य, संस्कृति, समाज व देश में कुछ अभिनव होगा।

साहित्योत्सव के समेकित परिचर्चाओं पर अगर दृष्टि डालें तो इसका संपूर्ण कार्यक्रम बहुत ही लुभावना लगा। प्रत्येक विधा को महत्व दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्डी को सम्मानित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है जिससे इनकी सर्जन की ओज से पूरा कार्यक्रम प्रभावी बने। केवल कविता, कहानी, उपन्यास, व्यंग्य आदि में स्थापित साहित्य सेवियों को ही नहीं आमंत्रित किया गया बल्कि देश के सुप्रसिद्ध चिंतकों, साहित्य अकादमी अवॉर्ड प्राप्तकर्ताओं और नेतृत्वकर्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी स्थान देकर इसको श्रेष्ठ आयोजन बनाया गया है। साहित्योत्सव के इस महाकुंभ में निश्चय ही देश का प्रज्ञाशील समाज बहुत ही लाभान्वित होने जा रहा है।

एक समय था जब भारत में साहित्य रचने वाले बहुत ही बेचारगी के जीवन जीते थे। आज़ बाज़ार ने साहित्यकारों को भी अपने लिए नए नए दरवाजे खोल दिए हैं। वय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनेक साहित्यकारों ने चंद समय में काफी ख्याति अर्जित की है। सूचना प्रौद्योगिकी ने साहित्य को सुगम व सृजन को धन सम्पन्न बनाने में सहयोग प्रदान किया है। सिनेमा जगत में अनेक सहित्यसेवी अपनी कलम, स्याही व प्रज्ञा के बलबूते मनचाहा धन अर्जित कर रहे हैं। साहित्य में पहचान का संकट अब कम हुआ है। साहित्य अकादमी ने अनेक साहित्यकारों को नए पायदान देकर सदैव आगे बढ़ने हेतु सहयोग किया है। यह एक सात्विक व पुनीत भारतीय सेवा साहित्य अकादमी को बड़ा बनाती है और साहित्यकारों को पंख प्रदान करती है। यदि भारत में इस प्रकार के अभीष्ट अपना स्वरूप पाते रहे तो भारत की नीरसता दूर होगी। साहित्य की हलचल से देश में प्रगति के नए रास्ते सृजित होंगे। हमारे देश के इन सभी अभियान में लेकिन आज़ क्या नया हो सकता है, इसे अनुशासित तरीके से जिम्मेदारियां भी समझने की बारी है, यह भी इस आयोजन में शामिल लोगों को सोचना ज़रूरी है। स्वयं को आत्मावलोकित व प्रश्नांकित करके भी सच्चा साहित्यकार बहुत कुछ देश को दे जाता है यदि यह साहस भी इस महाकुंभ में प्रकट होता है तो निश्चय ही हम यह महसूस कर सकते हैं कि हम सभी एक बेहतरीन भारत गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

वन पर्यावरण

टाइगर स्टेट- बढ़ते रिजर्व और तस्करी का खतरा

भारत में बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन टाइगर बोन ग्लू जैसी अवैध तस्करी की गतिविधियाँ इन प्रयासों को चुनौती दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस गोंद की बढ़ती मांग बाघों के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। इससे उनकी सुरक्षा पर दबाव बढ़ रहा है।'

भारत एक ऐसा देश है, जो बाघों की सबसे बड़ी संख्या का घर है यहाँ विश्व की 75 फीसदी आबादी पाई जाती है। भारत सरकार के दीर्घकालिक प्रयासों के फलस्वरूप ही यह सफलता प्राप्त हुई है। भारत में बाघों की संरक्षण नीति को लेकर कई प्रयास किए गए हैं, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रमुख पहल है। इसका आरंभ भारत सरकार द्वारा 1973 में बाघों की घटती संख्या और उनके आवास के विनाश को रोकने के लिए किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने बाघों के लिए विशेष संरक्षित क्षेत्रों (टाइगर रिजर्व) की स्थापना की। वर्तमान में भारत में इन टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। 'टाइगर स्टेट' के रूप में ख्याति प्राप्त मध्यप्रदेश बाघों के संरक्षण को लेकर नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित करते हुए भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिससे टाइगर रिजर्व की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और बाघों के संरक्षण को एक नई दिशा मिल रही है जो कि बाघों के संरक्षण में एक बड़ी सफलता है।बाघों के संरक्षण के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है कि बाघ शीर्ष शिकारी हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं, शिकारियों की संख्या को नियंत्रित करते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। बाघों की अनुपस्थिति या उनकी संख्या में कमी से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो सकता है, जो वन्यजीवों और उनके आवासों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आईयूसीएन की सूची में जहां बाघों को लुप्तप्राय वहीं भारत के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में बाघों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के तौर पर शामिल किया गया है। इसी कारण बाघों का शिकार, अवैध शिकार, हत्या और व्यापार कड़ाई से निषेध है। इस अनुसूची में सूचीबद्ध जानवरों के खिलाफ अपराध करने पर कठोर दंड और सजा का प्रावधान भी है। मध्यप्रदेश के साथ ही सम्पूर्ण भारत में बढ़ते टाइगर रिजर्व का नेटवर्क जहां एक और तो प्रोजेक्ट टाइगर के सफल क्रियान्वयन को दर्शाता है वहीं सरकारों की प्रतिबद्धता और स्थानीय समुदायों की सकारात्मक सहभागिता भी दिखाता है। इतने प्रयासों के बावजूद भी बाघों का अवैध शिकार जारी है और हाल ही में मध्यप्रदेश के कटनी से एक कुख्यात शिकारी गिरोह को गिरफ्तार किया है जो बाघों की तस्करी कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहुँच बनाता है। इन बाघों कि तस्करी का कारण न केवल इसके खाल, दांत, पंजे या अन्य अंग बल्कि टाइगर बोन ग्लू भी है इसमें बाघ की हड्डियों को प्रेशर कुकर में पकाकर उससे चिपचिपा गोंद तैयार किया जाता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मांग है। यह एक प्रकार की पारंपरिक औषधि है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कुछ दक्षिण-एशियाई देशों में किया जाता है। यह गोंद मुख्य रूप से मांसपेशियों, जोड़ों के दर्द, रीढ़ की समस्याओं को ठीक करता है, ताकत बढ़ाता है और कामोत्तेजक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। हालांकि, यह अत्यंत दुर्लभ और अवैध वस्तु है, और इसका व्यापार बाघों की तस्करी को बढ़ावा देता है। इसके लिए बाघों की खेती भी की जाती है लेकिन जंगली बाघों से प्राप्त गोंद की प्रभावशीलता अधिक है जिससे उसकी कीमत भी ज्यादा है।

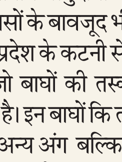

अस्मिता सिंह
लेखक शोध अध्येता

टाइगर बोन ग्लू का व्यापार मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क द्वारा संचालित होता है। चीन, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में बाघों के अंगों की मांग अधिक है, जो तस्करी के कारण भारत में बाघों की जनसंख्या पर प्रतिकूल असर डालती है। टाइगर बोन ग्लू की तस्करी भारत में बाघों के लिए एक गंभीर खतरा है। कई राज्य, विशेष रूप से मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा, इस तस्करी से प्रभावित हैं।

भारत सरकार और वन्यजीव संरक्षण संगठनों ने इस तस्करी को रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं। वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है और कई अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और संस्थाएं भी अस्तित्व में हैं, जैसे कि सीआईटीईएस, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, सेव द टाइगर फंड, नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथारिटी आदि, जो बाघों के अंगों के राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती है। बावजूद इसके, तस्करी के रास्ते अभी भी खुले हैं, और यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बाघों की सुरक्षा और संरक्षण की प्रक्रिया में सरकार, गैर-सरकारी संस्थाएँ, स्थानीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि बाघों के संरक्षण में कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन यह सहयोग और संयुक्त प्रयासों के माध्यम से संभव है कि हम बाघों की संख्या बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन संस्थाओं द्वारा किए गए कदमों से बाघों के संरक्षण के प्रयासों में लगातार सफलता मिल रही है, लेकिन इससे जुड़ी तस्करी, शिकार और मानव-बाघ संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए और भी अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

प्राकृतिक रंगों से सुरक्षित और खुशहाल होली

होली विशेष

डॉ. मोनिका राज
लेखक स्तंभकार हैं।

होली भारत के सबसे रंगीन और उल्लासपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह केवल रंगों और उमंग का पर्व नहीं, बल्कि भाईचारे, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक भी है। इस दिन लोग सभी गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं और मिलकर आनंद मनाते हैं। परंपरागत रूप से यह त्योहार प्राकृतिक रंगों से खेला जाता था, जो फूलों, फलों, पत्तियों और मसालों से बनाए जाते थे। ये रंग न केवल हमारी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होते थे, बल्कि पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे।

लेकिन आधुनिकता के प्रभाव में होली के रंग भी बदल गए हैं। बाजार में मिलने वाले अधिकतर रंग रासायनिक होते हैं, जिनमें लेड, मरकरी, क्रोमियम, बेंजीन और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं। ये रंग त्वचा और बालों को नुकसान पहुँचाते हैं, आँखों में जलन पैदा करते हैं, श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। इसके अलावा, ये रंग पानी के स्रोतों और मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया है कि हम प्राकृतिक रंगों की ओर लौटें और पारंपरिक होली का आनंद लें। इससे न केवल हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि हम पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकेंगे।

प्राकृतिक रंगों के कई लाभ हैं। ये रंग फूलों, पत्तियों, फलों और मसालों से बनाए जाते हैं, जो त्वचा पर कोमल होते हैं। इनमें मौजूद प्राकृतिक तत्व एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। जैसे गुलाल (पलाश के फूलों से बना) त्वचा पर ठंडक पहुँचाता है, हल्दी त्वचा के लिए एंटीसेप्टिक का काम करती है, चुकंदर से बना लाल रंग त्वचा को निखारता है और फ्री रेडिकल्स से बचाव करता है। नीम और मेंहदी से बने हरे रंग त्वचा संबंधी रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। इन प्राकृतिक रंगों से होली खेलने से न केवल हमारी त्वचा सुरक्षित रहती है, बल्कि आँखों, श्वसन तंत्र और बालों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता।

इसके अलावा, प्राकृतिक रंग पर्यावरण-अनुकूल होते हैं और आसानी से अपघटित हो जाते हैं। ये पानी में घुलकर नदियों और झीलों को प्रदूषित नहीं करते, जिससे जलीय जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत, रासायनिक रंगों में मौजूद भारी धातुएँ और जहरीले तत्व जलस्रोतों को दूषित करते हैं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं। प्राकृतिक रंगों का उपयोग न केवल हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक है, बल्कि जल और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी मदद करता है।आज के समय में बाजार में मिलने वाले अधिकतर होली के रंग रासायनिक होते हैं, जिनमें लेड ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड, क्रोमियम आयोडाइड जैसे खतरनाक तत्व होते हैं। ये तत्व त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, एलर्जी और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा, आँखों में जाने पर ये रंग जलन, लालिमा और सूजन उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ मामलों में यह कंजेक्टिवाइटिस जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। श्वसन तंत्र पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रंगों के सूक्ष्म कण साँस के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी जैसी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं। लंबे समय तक इन रासायनिक रंगों के संपर्क में रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ भी हो सकती हैं।

पर्यावरण के संदर्भ में भी रासायनिक रंग बेहद हानिकारक हैं। ये रंग पानी में घुलकर नदियों, झीलों और अन्य जलस्रोतों को प्रदूषित करते हैं। इससे जलीय जीवों के जीवन पर संकट आ जाता है और मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। यह स्थिति हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक है। इसलिए, यह आवश्यक हो गया है कि हम रासायनिक रंगों से बचाव करें और प्राकृतिक रंगों का अधिकाधिक उपयोग करें।रासायनिक रंगों से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। बाजार में हर्बल रंग आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन यदि संभव हो तो घर पर ही प्राकृतिक रंग बनाए जाएँ। चुकंदर से गुलाबी रंग, हल्दी और बेसन से पीला रंग, पुदीना, पालक या नीम की पत्तियों से हरा रंग और पलाश के फूलों से लाल रंग आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अलावा, होली खेलने से पहले त्वचा पर नारियल या सरसों का तेल लगाना चाहिए, ताकि रंग आसानी से छुड़ाया जा सके। बालों की सुरक्षा के लिए तेल लगाकर टोपी पहनना और आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का उपयोग करना उचित रहेगा।होली के दौरान जल संरक्षण पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। रंग छुड़ाने के लिए अधिक पानी बर्बाद करने के बजाय सूखे गुलाल से होली खेलना और प्राकृतिक उपायों से रंग साफ करना बेहतर होगा। हमें यह समझना होगा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर है।

अफीम की अवैध खेती का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

30 हजार की अफीम और हिरण की खाल बरामद

बैतूल। पुलिस ने अफीम की अवैध खेती के मामले में फरार 20 हजार रुपए के इनामी आरोपी गोपाल बंजारा को गिरफ्तार किया है। उसे जिले में अफीम की खेती का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। गोपाल अफीम तस्करी का अंतरराज्यीय तस्कर है। उस पर राजस्थान के चित्तौडग़ढ़ और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भी तस्करी के पांच मामले दर्ज हैं। वह पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। पुलिस उसका रिमांड लेकर पूछताछ करेगी, जिससे इस तस्करी के और भी कडिय़ां जुडऩे की उम्मीद है। सारणी पुलिस ने गोपाल को पकडक़र उसके पास से 30 हजार रुपए कीमत की अफीम, एक हिरण की खाल और अवैध पिस्तौल, कारतूस भी बरामद किए हैं। एसपी निश्चल एन झारिया के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोपना की तरफ से एक व्यक्ति पाथाखेड़ा की ओर आ रहा है, जिसका नाम गोपाल बंजारा पिता मांगीलाल बंजारा (31) है। वह अवैध मादक पदार्थ, वन्य जीव खाल तस्करी और अवैध हथियार एक बैग में रखकर पैदल आ रहा है। इस सूचना पर विशेष टीम का गठन कर मौके पर घेराबंदी कर गोपाल को पकड़ लिया गया। आरोपी के खिलाफ राजस्थान के चित्तौडग़ढ़ और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में तस्करी के पांच मामले दर्ज हैं। वहीं, बैतूल जिले में अफीम की अवैध खेती के कई मामले दर्ज हैं।

ग्रामों और किसानों के बजाय ब्लूबेरी कंपनी को मिल रहा वर्धा बांध का पानी

विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और कमिश्नर से की शिकायत

बैतूल/मुलताई। मुलताई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शेरगढ़ में करोड़ों की लागत से बनाई गई बहुउद्देशीय वर्धा बांध के पानी का उपयोग निजी ब्लूबेरी कंपनी 400 एकड़ भूमि पर ब्लूबेरी उत्पादन के लिए कर रही है। ब्लूबेरी कंपनी वर्धा बांध के पानी का दोहन किस रफ्तार से कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सलाईढाना और हरदौली के बीच कप्पी क्षेत्र, जहां बड़ी-बड़ी मोटर लगाकर कंपनी पानी ले रही है। यह भाग अब लगभग सूख चुका है और जानकार बताते हैं कि कंपनी इसके आगे के भाग में मोटर डालने की योजना बना रही है। पहले ब्लूबेरी कंपनी वर्धा बांध के पानी का उपयोग अवैध रूप से कर रही थी। शिकायतों के बाद अब सिंचाई विभाग से अनुबंध किया तो अनुबंध से कई अधिक जल का उपयोग कर रही है। दूसरी ओर बांध क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सिंचाई अधिकारियों और कंपनी के हौसलों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस संबंध में स्थानीय विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने मुख्यमंत्री को पत्र लिकर ब्लूबेरी को पानी उपलब्ध कराने से ग्रामों में जल संकट उत्पन्न होने की आशंका जताई है, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार ने भी इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं कमिश्नर को पत्र लिखा है, किंतु उसके बावजूद भी

ब्लूबेरी कंपनी बिना रोक-टोक बड़ी-बड़ी मशीन लगाकर वर्धा बांध से पानी ले रही है।

किसानों से बेरुखी, कंपनी पर मेहरबान सिंचाई विभाग ....

वर्धा बांध क्षेत्र के ग्राम सलाईढाना के किसान चंदन बरखाडे, उदल बरखाडे, जंगली कोडले, रामदास सूर्यवंशी एवं ग्राम कोडर के गुड्डू महाजन, मारुति बेले, श्रीराम बेले, लाल जी साहू, राहुल फरकाडे, बताते हैं कि सिंचाई विभाग किसानों को पानी उपलब्ध कराने के बजाय ब्लूबेरी कंपनी को बिना नापतोल बगैर मीटर लगाए पानी उपलब्ध करा रहा है। कंपनी जहां से पानी ले रही थी, वह भाग पूरा सूख गया है, किंतु जब बात किसानों को पानी उपलब्ध कराने की होती है। सिंचाई विभाग वर्धा नदी में पानी छोड़ कर बहां देते है, लेकिन किसानों को उपलब्ध नहीं कराते इस वर्ष गेहूं की फसल के लिए किसानों को दो पानी की आवश्यकता थी, किंतु किसान बांध के जिस क्षेत्र से पानी लेते थे वहां का पानी वर्धा नदी में छोड़ दिया।

8 साल बाद भी अधर में लटकी वर्धा परियोजना ....

मुलताई विधानसभा क्षेत्र के 102 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने और 5700 हेक्टर रकबे को संचित करने के उद्देश्य से ग्राम शेरगढ़ के पास वर्धा नदी पर 155 करोड़ की लागत से बनाई गई बहुउद्देशीय वर्धा सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन हुए लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं, किंतु नव वर्ष बाद भी वर्धा परियोजना अधूरी है। जानकार बताते हैं कि समय सीमा में कार्य पूर्ण ना करने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत के चलते तरह-तरह के तथ्यहीन कारण बताकर ठेकेदार की समय सीमा बढ़ाई जाती रही है। नतीजा यह है कि इस योजना का संपूर्ण लाभ अब तक क्षेत्र को नहीं मिल रहा है। वर्धा बांध का पानी किसानों एवं पेयजल के लिए ग्रामों को उपलब्ध कराने की बजाय ब्लूबेरी कंपनी को देने और बगैर मॉनिटरिंग करें अनुबंध से अधिक पानी का उपयोग करने को लेकर सिंचाई अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। सिंचाई विभाग से किए गए अनुबंध से अधिक पानी का उपयोग ब्लूबेरी उत्पादन के लिए कर रही है। जिसके चलते 102 ग्रामों में जल संकट की स्थिति निर्मित होने की आशंका जताई जा रही है और इसको लेकर स्थानीय विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने जहां मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की है।

इनका कहना -

ब्लूबेरी कंपनी के साथ जो अनुबंध हुआ है, उसके हिसाब से ही वर्धा बांध का पानी कंपनी ले रही है। जहां तक किसान के बजाय कंपनी को पानी उपलब्ध कराने का सवाल है तो विभाग अभी वर्धा बांध में पूरा पानी स्टोर नहीं कर रहा है। नेताओं ने जहां शिकायत या पत्र लिखा है, तो सीएम से जांच अधिकारी आ जाएंगे, तो जांच हो जाएगी।

मनोज चौहान एसडीओ जल संसाधन विभाग मुलताई

हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर की मौत

बैतूल। बैतूल में बालाजी ट्रांसपोर्ट के 23 वर्षीय ड्राइवर की हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। ड्राइवर विजय प्रयाग बारहवीं गांव का रहने वाला था। ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक सूरज दुबे के अनुसार, युवक जब काम पर आया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गया। लंबे समय तक नहीं उठने पर अन्य स्टाफ ने उसकी स्थिति की जांच की। मंगलवार शाम करीब 4 बजे उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। उस समय वह बेहोश था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के लगभग आधे घंटे बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके दिमाग और हृदय में रक्त के थक्के पाए गए। डॉक्टरों का मानना है कि उच्च रक्तचाप के कारण उसे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हुआ। युवक इटारसी रोड पर किराए के कमरे में रहता था।

बैतूल जेल में कैदी की मौत, 3 दिन पहले भेजा गया था जेल

पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया आरोप

बैतूल। बैतूल जेल में बंद एक कैदी की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक अशोक वासुदेव खांडे (44) को पिछले 9 मार्च को धारा 144 बीएनएसएस के तहत भरण-पोषण मामले में न्यायालय से जेल लाया गया था। जेल अधीक्षक योगेन्द्र तिवारी के अनुसार बुधवार दोपहर अशोक जेल की बैरक में बैठा हुआ था। अचानक उसे घबराहट हुई और वह बेहोश होकर गिर गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक बिल्डिंग मैटेरियल सप्लाई का काम करता था। उसकी शादी 20 साल पहले सारणी में हुई थी। घरेलू विवाद के कारण उसकी पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद पत्नी ने उसके खिलाफ भरण-पोषण का मामला दर्ज करा दिया था। मृतक की दूसरी पत्नी रेणुका ने आरोप लगाया है कि उसके पति के सीने में लंबे समय से लगातार दर्द हो रहा था। उन्होंने दर्द की शिकायत की थी, लेकिन जेल प्रबंधन ने उनका इलाज नहीं कराया। जेल प्रबंधन उनकी बातों को बहानेबाजी ही समझता रहा, जबकि उन्हें हृदय की समस्या हो रही थी।

बैतूल रेलवे स्टेशन की पार्किंग में मिला बुजुर्ग का शव

बैतूल। बैतूल रेलवे स्टेशन की पार्किंग में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान सेलगांव निवासी फूलचंद बाबू नावडे के रूप में हुई है। वह 55 वर्ष के थे और गंज क्षेत्र में हमाली का काम करते थे। बुधवार को स्टेशन की पार्किंग में लोगों ने एक बुजुर्ग को संदिग्ध हालत में पड़ा देखा। उन्होंने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने एंबुलेंस को खबर दी। एंबुलेंस से बुजुर्ग को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि फूलचंद गांव से बैतूल आता जाता रहता था। उसके परिजनों को बैतूल बुलवाया गया है। जिसके बाद ही उसका विस्तृत विवरण मिल सकेगा। फिलहाल मृतक का पीएम नहीं हो सका है। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस उसका शव परीक्षण करवाएगी।

बैतूल विधायक के प्रयास से विधानसभा क्षेत्र में साढ़े 13 किमी की पांच सड़कें स्वीकृत

बजट में 13.37 करोड़ रूपये की मिली स्वीकृति, हजारों ग्रामीणों के लिए आवागमन होगा सुलभ

बैतूल। आमजन को मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध बैतूल विधायक हेमन्त खण्डेलवाल के विशेष प्रयासों से बैतूल विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में साढे 13 किमी की पॉच सडके स्वीकृत हुई है। उक्त सडकों के निर्माण के लिए वार्षिक बजट में 13 करोड 37 लाख 82 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। 12 मार्च 2025 को मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री श्री जगदीश देवडा द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए वार्षिक बजट में सडकों के निर्माण के लिए उक्त राशि का प्रावधान किया गया है। पक्की सडकों का निर्माण होने से हजारों ग्रामीणो को जर्जर सडकों से मुक्ति मिलेगी और आवागमन सुलभ होगा। उक्त सडको की स्वीकृति के लिए क्षेत्र की जनता ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव , उपमुख्यमंत्री- वित्त मंत्री जगदीश देवडा एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह का आभार व्यक्त किया है।

एक होली ऐसी भी, सिकलसेल और थेलेसिमिया पीड़ित बच्चों को फल, ड्राय फ्रूट, पिचकारी और बलून बाटकर मनाई

जन्मदिन पर केक नहीं दूसरो का दुख काट

बैतूल। जिला चिकित्सालय में भर्ती सिकलसेल और थेलेसिमिया से पीडित बच्चों के दर्द की कल्पना नहीं की जा सकती। इन मासूमों का कोई भी त्योहार हो हॉस्पिटल में ही मनता है, इनके लिए क्या दिवाली क्या होली लेकिन इन बच्चों का दर्द साझा करने मां शारदा सहायता समिति के संरक्षक संजय शुक्ला के जन्मदिन पर जिला चिकित्सालय में अभिनव कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के शैलेंद्र बिहारिया और पंजाबराव गायकवाड ने बताया कि इस होली पर इन मासूमों का दर्द साझा करने अध्यक्ष पिंकी भाटिया, हिमांशु सोनी, बंडू लिखितकर, राजेश बोरखड़े ने इन बच्चों के पास पहुंचकर होली पर उपहार दिया जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश घोरे, डॉ.रानू वर्मा, संजय शुक्ला उपस्थित थे। सभी ने इन मासूम बच्चो को फल, ड्राय फूड, पिचकारी, बलून पैकेट बाटकर होली की शुभकामनाएं प्रेषित की। सभी ने इनके परिजनों से इनका दर्द साझा किया। कुमारी लता की माता ने बताया की लता को थेलेसिमिया है। बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, कोई भी त्योहार हो अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और त्योहार पर भी हम दर्द से लड़ते रहते है ऐसे में आप लोगो का साथ बच्चो के चेहरे पर खुशी लेकर आता है इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश घोरे ने कहा की इस तरह के आयोजन से बच्चों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। यह पीड़ित मानवता की सेवा में सार्थक प्रयास है। डॉक्टर रानू वर्मा ने कहा आओ चुपके से खुशियां रख आए उनके सिरहाने में जिन्हे वर्षो लगे मुस्कुराने में, उन्होंने ऐसे बच्चों को अपने हाथों से पिचकारी बाट दुलार किया।

मोबाइल टावर लगाने का विरोध, सोशल मीडिया रेडिएशन की संभावना जताई, दो वार्डों में हैं केंसर पीड़ित

हीरालाल गोलानी सोहागपुर

जवाहर वार्ड के रिहायशी इलाके में एक निजी भूमि पर मोबाइल टावर लगाने का नागरिकों ने पुरजोर विरोध किया है। इस टावर लगाने का आज दोपहर जवाहर वार्ड वासियों ने विरोध करते अनुविभागीय अधिकारी को सूचना दी। वहीं इसी संबंध में जवाहर वार्ड पार्षद अमृता चौरसिया,कामेश साहू , पूर्व पार्षद राकेश चौरसिया आदि ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जवाहर वार्ड में रहवासी इलाके में ऐ.टी.सी कंपनी का मोबाइल टावर अवैध से बनाया जा रहा है।यह वार्ड घनी आवादी वाला रहवासी क्षेत्र है। जिसमें सभी के घर एक दूसरे से लगे हुए है । उक्त टावर के आबादी में लगने के कारण रहवासियों के स्वास्थ पर बुरा असर पड़ेगा ।तथा मोबाइल टावर के निकालने वाली रेडिएसन के बच्चें एवं बुजुर्गो के स्वास्थ पर भी विपरीत असर पड़ेगा। उल्लेखनीय यह भी है कि जवाहर वार्ड में नगर के सब से अधिक कैंसर की बीमारी, दिल

की बीमारी तथा सांस की बीमारी के मरीज है।इसकी सूचना जानकारी स्वास्थ विभाग सोहागपुर के रिकॉर्ड में दर्ज है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कंपनी के टावर के करीब लगभग 10 फिट की दूरी पर ही पूर्व मे भी रिलायंस जी.ओ का टावर लगा हुआ है। रिलायंस जी.ओ के टावर लगाते समय भी जवाहर वार्ड के निवासीयों द्वारा विरोध किया गया था। किन्तु उक्त कंपनी के रसूक के कारण पूर्व में टावर लग गया था। उक्त टावर से आस-पास में रहने वाले तीन लोगों कि मौत हो गई है। लगभग 30-40 व्यक्तियों को श्वास की बीमारी की तकलीफ हो गई है। पूर्व में लगे जी.ओ. कंपनी का टावर भूतल पर लगा है ।जिससे तेज ध्वनि निकलती है । इससे आस-पास के लोगो को बहुत अधिक तकलीफ होने के साथ छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी बाधित होती है। इस टावर को भी भूतल के स्थान पर भवन के ऊपर सिफ्ट करवाया जाए। उपरोक्त ऐ.टी.एस कंपनी के टावर को यदि नहीं रोका गया।इस स्थिति में जवाहर वार्डवासी महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे एस.डी.एम कार्यालय के सामने धरना, सत्याग्रह करेंगे इसकी सारी जबाबदारी प्रशासन की होगी। इसी संबंध को लेकर एक सोशल मीडिया ग्रुप पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वकील देवान्शु शर्मा ने लिख है कि प्रशासन यदि इस पर रोक नहीं लगाता है।ऐसी स्थिति में वार्डवासी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाए।नगर हित और समाज हित के लिए एक प्रति उपलब्ध कराए मेरे द्वारा स्टे की प्रक्रिया फाइल की जाएगी। निश्चित ही इस रेडिएशन के खतरे से शहर को सुरक्षित किया जाएगा। यदि अभी नहीं रोका गया तो यह कंपनी वाले पूरे शहर में टावर लगाकर सभी के जीवन को खतरे में डाल देंगे..और जो लोग थोड़े से आर्थिक फायदे के लिए कंपनी बालों की बातों में आ जाते है । वो स्वयं समझदार है कि इस तरह रेडिएशन से आपको भी नुकसान होगा।अत: इस तरह रहवासियों क्षेत्रों में टावर लगाने की प्रक्रिया पर सख्त पाबंदी लगे।

अब दिखने लगी दुनिया, नेत्र ऑपरेशन से 36 मरीज लाभान्वित

लायंस क्लब भौरा का प्रयास, अब दिखेगी दुनिया पहले से बेहतर

बैतूल-/भौरा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भौरा में सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय के ऑफटो मेडिसिन वृंदावन शर्मा ने मोतियाबिंद ऑपरेशन कराए गए 36 मरीजों की पुनः जांच की। सभी मरीजों की स्थिति सामान्य पाई गई। डॉक्टरों ने उन्हें आवश्यक दवाएं और देखभाल के निर्देश दिए। इन मरीजों को 3 मार्च को लायंस क्लब भौरा द्वारा आयोजित नेत्र एवं मधुमेह जांच शिविर में चिन्हित किया गया था। ऑपरेशन के लिए इन्हें बैरागढ़ स्थित सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय भेजा गया था। 5 मार्च को सभी मरीजों को भौरा वापस लाया गया। 3 मार्च को हुए शिविर में 90 से अधिक लोगों ने आंखों और मधुमेह की जांच कराई थी। इनमें से 40 मरीजों में मोतियाबिंद की पुष्टि हुई। ऑपरेशन के लिए 36 मरीजों को चुना गया। लायंस क्लब भौरा ने इन्हें विशेष बस से बैरागढ़ भेजा। सेवा सदन चिकित्सालय में इनका सफल ऑपरेशन किया गया। चार मरीजों का ऑपरेशन शुगर और हाई ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण नहीं हो

सका। 5 मार्च को मरीजों को भौरा लाकर मंगलवार को उनकी पुनः जांच की गई। सभी की स्थिति सामान्य पाई गई।

परिजनों ने जताया आभार..............

मोतियाबिंद ऑपरेशन से लाभान्वित मरीजों और उनके परिजनों ने लायंस क्लब और सेवा सदन चिकित्सालय का आभार जताया। रामप्रसाद उईके, उम्र 62, ग्राम गुरगुंदा ने कहा, पिछले कुछ महीनों से धुंधला दिख रहा था। काम में दिक्कत हो रही थी। अब सब साफ दिखने लगा है। यह सेवा सदन और लायंस क्लब की वजह से संभव हुआ। भागरती बाई, उम्र 60, ने कहा, डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो नजर और कम हो जाएगी। पहले डर लग रहा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।

सेवा सदन चिकित्सालय की टीम ने निभाई अहम भूमिका...सेवा सदन चिकित्सालय की टीम ने मरीजों की नेत्र जांच, दवाई वितरण और ऑपरेशन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। टीम में डॉ. मायुरेश राठौर, निखिल केवट, मीलिंग, अनिकेत मौर्य, मोहन मेहरा और नीरज दुबे शामिल थे, ने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र रोग की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जागरूकता की कमी के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते। इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों तक चिकित्सा सहायता पहुंचाना था, जो सफल रहा।

लायंस क्लब ने निभाई समाजसेवा की जिम्मेदारी
.लायंस क्लब भौरा के अध्यक्ष राजेंद्र साहू, प्रेम उदयपुरे, राजेंद्र सिरोठिया, अशोक अग्रवाल, पराग राठौर, संतोष नायक और संजय शुक्ला ने कहा, क्लब हमेशा समाजसेवा के कार्यों के लिए तत्पर रहता है। इस शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करना हमारा मुख्य उद्देश्य था। भविष्य में भी इस तरह के निश्शुल्क शिविर आयोजित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। भौरा और आसपास के ग्रामीणों ने इस अभियान की सराहना की। कई लोगों ने कहा कि ऐसे शिविर उन लोगों के लिए जीवन बदलने का काम करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सही इलाज तक नहीं पहुंच पाते।

शेखरचंद लेफ्टिनेंट बने

बैतूल। सेना में किसी युवक का चयन होने पर उसका परिवार ही नहीं पूरा गांव आपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देना किसी के लिए भी बहुत सम्मान का क्षण होता है। ग्राम दनोरा भडूस निवासी सेवानिवृत्त सैनिक हीरालाल-श्रीमती गीता मालवी के पुत्र शेखरचन्द्र मालवी का भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। शेखरचन्द की प्रथम पोस्टिंग गोहाटी असम की आर्टी रेजिमेंट में हुई है। श्री मालवी के चयन होने से गांव के युवकों को भी प्रेरणा मिलेगी। इनके चयनित होने पर पूरे गांव में हर्ष व्याप्त है। शेखर चंद जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत नारायण खवादे के भतीजे हैं। इनकी नियुक्ति पर श्रीराम खवादे, दिलीप खवादे, दशरथ खवादे, रामेश्वर खवादे, झनक खवादे, अंशुल खवादे, खुशांक खवादे, कृष्णा खवादे, सेन समाज के पदाधिकारियों, सदस्यों सहित इष्ट मित्रों और परिजनों ने बधाई दी है।

कलेक्टर ने जिले में भिक्षावृत्ति पर लगाया प्रतिबंध

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बैतूल जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। साथ ही भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार जिले में चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं या अपने परिवारों के साथ भिक्षावृत्ति की जाती है।

संक्रमण से जूझती महिला रेलवे लोको पायलट

बुनियादी

डॉ. प्रमोद शंकर सोनी
(लेखक व होम्योपैथिक चिकित्सक)

हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक महिला लोको पायलट के साथ एक बेहद दर्दनाक घटना उस समय घट गई जब इस महिला पायलट ने ट्रेन चलाने के दौरान नेचर्स कॉल को महसूस किया और इंजन में वॉशरूम की अनुपलब्धता के कारण उसे एक स्टेशन पर ट्रेन रोककर बाहर जाना पड़ा, तभी दूसरी ओर से अत्यंत तेज गति से आ रही ट्रेन ने उसे चीथड़ों में उड़ा दिया। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर रेलवे में महिला कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों पर अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं।

समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिला कर चलने वाली महिलाओं की भागीदारी भारतीय रेलवे में भी लगातार बढ़ रही है। आज महिलाएँ न केवल ट्रेन चला रही हैं, बल्कि रेलवे के हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और कौशल से नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, रेलवे में महिलाओं के वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं को आज भी अनदेखा करना बेहद दुखद है। शायद कम ही लोगों को ज्ञात होगा कि भारत में आज भी ट्रेन के इंजन में वॉशरूम नहीं बनाए जाते है जिसके पीछे कई तकनीकी और व्यावहारिक कारण दिए जाते हैं जैसे,

1. सुरक्षा कारण

इंजन का केबिन एक उच्च-जोखिम क्षेत्र होता है, जहां लोको पायलट को पूरे समय सतर्क रहना पड़ता है। अगर वॉशरूम मौजूद हो, तो इसका इस्तेमाल करने के दौरान ध्यान भटक सकता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है।

2. जगह की कमी

इंजन का केबिन काफी छोटा होता है, और वहां अधिकतर जगह आवश्यक कंट्रोल पैनल, उपकरण, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आरक्षित होती है। वॉशरूम के लिए जगह बनाना कठिन होता है।

3. ऑपरेशन में बाधा

ट्रेन इंजन में लगातार कंपन और झटके होते रहते हैं। ऐसे में वॉशरूम की पाइपलाइन और अन्य प्लंबिंग सिस्टम को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।

4. सफाई और रखरखाव

इंजन में वॉशरूम होने से उसकी सफाई और रखरखाव की अतिरिक्त समस्या उत्पन्न हो सकती है। इंजन को समय-समय पर अलग-अलग स्थानों पर बदला जाता है, और हर जगह सफाई की सुविधा सुनिश्चित करना मुश्किल होता है।यद्यपि, पुरुष लोको पायलट वॉशरूम संबंधित समस्या को अपनी शारीरिक बनावट के कारण किसी तरह सहन कर लेते हैं, लेकिन महिला लोको पायलटों के लिए इस तरह समस्या से निपटना बेहद कठिन होता। इंजन में वॉशरूम न होने की समस्या से महिला पायलट के लिए भारी असहज स्थिति पैदा हो जाती है और उन्हें घंटों तक अपनी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करना पड़ता है। पुरुष पायलट फिर भी किसी तरह सामंजस्य बिठा लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यह स्थिति शारीरिक और मानसिक रूप से कष्टदायक बन जाती है। यदि किसी महिला लोको पायलट को वॉशरूम जाना हो अथवा मासिक धर्म की अवस्था में पैड चेंज करना हो तो उसे कंट्रोल रूम और स्टेशन मास्टर से इस बात की अनुमति अनुमति लेनी पड़ती है। यह प्रक्रिया रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से होती है

जिससे अनेक पुरुष सहकर्मियों को इसकी जानकारी मिल जाती है जिससे वे भारी असहज महसूस करती हैं और उनके आत्मसम्मान को भी भारी ठेस पहुंचती है। इन्हीं सब प्रक्रियाओं से बचने के लिए महिला पायलेट कम से कम पानी का सेवन करती हैं जिससे उन्हें बार बार वॉशरूम का उपयोग न करना पड़े जिसके कारण उनके शरीर में गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं जिससे उन्हे डिहाइड्रेशन, मूत्रनली में संक्रमण (UTI), किडनी स्टोन,कब्ज ,पाइल्स जैसी अनेक बीमारियाँ होने का खतरा बढ़ जाता है।

पश्चिम बंगाल में उस महिला पायलट के साथ हुआ यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक व्यवस्था की लापरवाही और महिलाओं की जरूरतों के प्रति असंवेदनशीलता का परिणाम है जिसे जल्दी से जल्दी दूर करने की महती आवश्यकता है।

रेलवे द्वारा क्या किया जा सकता है।

* माना कि इंजन रूम छोटा होने से समस्याएं पैदा होती हैं पर इसके निवारण के लिए इंजन में पोर्टेबल वॉशरूम लगाने की व्यवस्था की जा सकती है। इंजन में छोटे बायो-टॉयलेट स्थापित किए जा सकते हैं। जिससे महिला लोको पायलटों को यह असहज स्थिति न झेलनी पड़े।
* **स्टेशनों पर विशेष महिला वॉशरूम:** रेलवे को हर प्रमुख स्टेशन पर विशेष महिला वॉशरूम बनवाने चाहिए, जहाँ महिला लोको पायलट सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में अपनी जरूरत पूरी कर सकें।
* **नए इंजनों में वॉशरूम की अनिवार्यता**-भविष्य में बनने वाले सभी नए इंजनों में वॉशरूम की सुविधा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि यह समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जाए। इंजन की डिजाइन इस तरह की जाए कि एआई की मदद से ऑटो मॉड पर ट्रेन चलते हुए भी दुर्घटना से बची रहे।
* **महिला कर्मचारियों के लिए नीति सुधार**-रेलवे को महिला लोको पायलटों की शिफ्ट और ड्यूटी प्लानिंग में लचीलापन लाना चाहिए, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए मजबूर न हों।

अगर हम चाहते हैं कि महिलाएँ हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो हमें उनके लिए सुरक्षित और सुविधाजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराना ही होगा। रेलवे को अब अपनी नीतियों में बदलाव लाकर महिला लोको पायलटों की इस बुनियादी आवश्यकता को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि इस तरह के दर्दनाक हादसे दुबारा न हों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल व पीड़ारहित वातावरण का निर्माण हो सके

केंद्रीय मंत्री शिवराज के बेटे का रिसेप्शन

संघ प्रमुख मोहन भागवत, सुरेश सोनी, भैयाजी जोशी पहुंचे

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की शादी के बाद आज भोपाल के जंबूरी मैदान पर रिसेप्शन है। समारोह में आशीर्वाद देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत, सुरेश सोनी, भैया जी जोशी, प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता, प्रांत संघचालक डॉ अशोक पाण्डेय पहुंचे।समारोह में बीजेपी के पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक सचिन बिरला, छाया मोरे, मंत्री कृष्णा गौर और संपतिया उईके आशीर्वाद देने पहुंचे। कृष्णा गौर को साधना सिंह ने गले लगाया।मप्र और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और सभी दलों के विधायकों को न्योता दिया गया है। इस समारोह में करीब दस हजार लोगों का भोज रखा गया है। जंबूरी मैदान और अवधपुरी जाने वाले रास्तें पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है।वर-वधु को आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर जाने वालों की लाइन लगी देखी गई हैं। आशीर्वाद समारोह में करीब 10 हजार लोगों को भोज रखा गया है।

देवी धाम सलकनपुर में प्रसादी की 15 दुकानों में लगी आग, लाखों रुपये का नुकसान

रेहटी (नप्र)। बुधवार को प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में दुकानों में आग लग गई, जिसमें लगभग 10 से 15 दुकान जलकर खाक हो गई। आग लगने की घटना सुबह लगभग 8.30 बजे की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह दुकानों

में आग जैसे ही लगी सभी दुकानदार मंदिर पहुंच गए और मंदिर पर चल रहे देवीलोक के निर्माण कार्य में लगे पानी के टैंकर और फ्लोरी में पानी भरकर बुलाया और दुकानदारों ने प्लास्टिक के कुप्पों से आग बुझाई। मंदिर की चढ़ाई ज्यादा होने की वजह से दमकल देर से पहुंच सकी।स्थानीय व्यापारी अरविंद मालवीय एवं पंकज शर्मा ने बताया कि आग तेजी से फैल रही थी। दुकानदारों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया।यदि आग को बुझाया नहीं गया होता तो लगभग सभी दुकानें आग में झुलस जाती। आग की रफ़्तार इतनी तेज थी कि रोड क्रास करके सामने वाली लाइन के पर्दे, बैनर और मेट भी आग में झुलस गए।मौके पहुंचे एसडीएम दिनेश तोमर, एसडीओपी बुदनी रवि शर्मा, तहसीलदार भूपेंद्र कैलाशिया, थाना प्रभारी राजेश कहारे, सलकनपुर चौकी प्रभारी भावना यादव, मंदिर ट्रस्ट सचिव रामकिशोर दुबे सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना का मौका मुआयना किया।पुलिस आग लगने के कारण की जांच कर रही है फिलहाल कारण अज्ञात है।

अक्सर होती रहती है आग लगने की घटना

2008 में सलकनपुर मंदिर के पास भेरू घाटी पर शार्टसर्किट से लगभग 40 दुकानें पूरी तरह जलकर ख़ाक हो गई थी। देखा गया कि दिवाली की रात भी मंदिर पर दुकानों में आग लगने की हुई है। इसका कारण कभी शार्टसर्किट तो कभी जंगल के सूखे पत्तों या दुकानों के अवशेष कचरे की वजह रहे हैं।

म.प्र.में सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन
स्क्रैप कराने पर मिलेगी 25 प्रतिशत तक टैक्स में छूट

भोपाल (नप्र)। बजट में 15 वर्ष आयु पूरी कर चुके सभी तरह के वाहनों को स्क्रैप कराना अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी (आरवीएसएफ) के तहत वाहनों का स्क्रैप कराया जा सकता है। यदि कोई शासकीय व निजी वाहन स्क्रैप कराता है तो उसे नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाएगी।

परिवहन विशेषज्ञ श्यामसुंदर शर्मा का कहना है कि इससे भोपाल सहित प्रदेश भर में बढ़ रहे वहनों की संख्या कमी आएगी। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी।

साथ ही पेट्रोल, डीजल के ऐसे वाहन जिनकी उम्र 15 वर्ष हो चुकी है, वो स्क्रैप होने से पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। कई ऐसे वाहन हैं, जो धुंआ छोड़कर वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इससे आसपास का वातावरण अशुद्ध होता है, लेकिन इसमें वाहनों की स्थिति भी देखी जानी चाहिए। यदि वाहन टीक है तो उसे स्क्रैप के दायरे से बाहर किया जाए। कई ऐसे लोग होते हैं, जो आत्मीय रूप से वाहनों से जुड़ जाते हैं और उनके वाहनों की पीयूसी व फिटनेस ठीक रहती है। बजट में सबसे अच्छी बात यह है पुराने वाहनों को स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने पर मोटरयान कर यानि टैक्स में छूट मिलेगी। परिवहन वाहनों में 15 प्रतिशत और गैर परिवहन वाहनों में 25 प्रतिशत तक की टैक्स में छूट देने का प्रविधान किया गया है।

संजय यादव राजाभोज शोध प्रभाग के निदेशक मनोनीत

भोपाल। 'महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ' के राजाभोज शोध प्रभाग का संजय यादव को निदेशक मनोनीत किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजा भोज शोध प्रभाग द्वारा तैयार की गयी राजा भोज पर केन्द्रित झॉंकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संस्कृति विभाग के आदेश के अनुसार राज्य शासन एतद द्वारा संजय यादव पूर्व निदेशक, धर्मपाल शोध पीठ एवं सेवानिवृत्त सहायक संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्थापित महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के राजा भोज शोध प्रभाग, भोपाल में निदेशक के पद पर 02 वर्ष अथवा आगामी आदेश (जो भी पहले हो) तक के लिए मनोनीत किया जाता है।

कायस्थम का होली मिलन 'रंग बरसे' कार्यक्रम 15 मार्च

भोपाल। कायस्थ समाज की अग्रणी संस्था कायस्थम भोपाल द्वारा होली के दूसरे दिन 15 मार्च को शाम 4 बजे से होली मिलन कार्यक्रम 'रंग बरसे' आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्य और अन्य चित्रांश बंधु एक-दूसरे को गुलाल लगाकर फूलों से होली खेलेंगे तथा एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देंगे। होली के सुमधुर गीतों की प्रस्तुति भी होगी। कायस्थम के महासचिव अभय श्रीवास्तव, सचिव डॉ. रश्मि सक्सेना ने बताया कि भोपाल हाट बाजार के पीछे 9 मसाला के उद्यान में शाम 4:00 बजे से 7:00 तक होली मिलन 'रंग बरसे' का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

'होरी हो ब्रजराज' के फागुनी रंगों से महकेगी वादियां

भोपाल। होली के पारम्परिक गीत-संगीत और नृत्य के वासंती रंग 18 मार्च की शाम 6:30 बजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के मुक्ताकाश में बिखरेंगे। टैगोर लोक कला एवं संस्कृति केन्द्र, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा 'होरी हो ब्रजराज' का रंगारंग आयोजन मानव संग्रहालय, विश्वरंग फाउंडेशन, स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी, वनमाली सृजनपीठ तथा पुरू कथक अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है। लोक रंगों में छलकती फागुनी छवियों की यह दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना क्षमा मालवीय के निर्देशन में मंचित होगी। इस प्रदर्शन में शहर के 50 से भी ज़्यादा कलाकार हिस्सा लेंगे। इस रूपक की मूल संकल्पना कवि-कथाकार संतोष चौबे ने की है। वाचिक स्वर कला समीक्षक विनय उपाध्याय का है। संगीत संयोजन संगीतकार संतोष कौशिक ने किया है। होली की दृश्य-छवियों पर केन्द्रित चित्र प्रदर्शनी 'बिम्ब-प्रतिबिम्ब' भी आकर्षण का केन्द्र होगी। प्रस्तुति में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क है।

आरएनटीयू में 'भाषा संवाद' का आयोजन

भोपाल।न्यू जर्सी (अमेरिका) स्थित युवा हिंदी संस्थान और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रयास से विकसित फुलब्राइट-हेस जी पी ए हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण परियोजना के बीस सदस्यीय दल ने रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल की मेजबानी में आयोजित 'भाषा संवाद' एवं विविध कार्यक्रमों में रचनात्मक भागीदारी की। उल्लेखनीय है कि इस अध्ययन दल में अमेरिका के ग्यारह विश्वविद्यालयों के हिंदी विशेषज्ञों, प्राध्यापकों ने रचनात्मक भागीदारी की।

इस अवसर पर विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलम्पियाड-2025 के पोस्टर का लोकार्पण अतिथियों द्वारा किया गया। प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केन्द्र द्वारा तैयार एवं आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित 'अमेरिका की चयनित रचनाएँ' पुस्तक का लोकार्पण भी इस अवसर अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन- संचालन अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र के निदेशक डॉक्टर जवाहर कर्णावट ने किया।

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलाधिपति एवं विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने कहा कि राष्ट्र प्रेम, मातृभाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था के कारण विदेशों में प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों ने

वैश्विक स्तर पर न सिर्फ हिंदी को बचाए रखा है वरन उसके विस्तार की नई संभावनाओं को जन्म दिया है। टैगोर विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी।

फुलब्राइट-हेस जी पी ए परियोजना के कार्यक्रम निदेशक अशोक ओझा ने कहा कि युवा हिंदी संस्थान और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फुलब्राइट-हेस जी पी ए परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि अमेरिकी भाषा शिक्षकों और वहाँ शिक्षक-प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति का औपचारिक ज्ञान प्राप्त हो, ताकि वे अमेरिका लौटकर उन सांस्कृतिक विषयों पर हिंदी में उत्कृष्ट पाठ्यक्रम तैयार कर सकें।

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में हिंदी की वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफ़ेसर गैब्रिएला निक इलेवा ने 'भारत की लोक संस्कृति में कहानी के विविध आयाम और ऐतिहासिक स्थापत्य स्थलों में मूर्ति कला द्वारा प्रस्तुत कहानियाँ' पर विचार प्रस्तुत किये।

डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स, प्रति कुलाधिपति, आर.एन.टी.यू. ने इस अवसर पर आईसेक्ट नेटवर्क और एजीयू की विगत चालीस वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला।

प्रो. अमिताभ सक्सेना ने नींव पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रो. आर.पी.दुबे, कुलपति, आर.एन.टी.यू. ने भी हिंदी शिक्षण पर अपने विचार रखे। आभार संजय सिंह राठौर, सचिव, विश्व रंग सचिवालय ने व्यक्त किया।

राजधानी में बुधवार को अंगदान जागरण रैली राजभवन से गांधी भवन तक निकाली गई।

शहीद भगतसिंह क्लब द्वारा होली पर कलात्मक रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन 13 और 14 को

मोहन वर्मा/देवास। रंगों के त्यौहार, होली के अवसर पर रांगोली, चित्रण मध्यप्रदेश में सीर्फ देवास की ही अनोखी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। शहीद भगतसिंह क्लब के संयोजक श्री अशोक कहार ने बताया कि, क्लब यह आयोजन विगत 15 वर्षों से लगातार करता आ रहा है। प्रख्यात चित्रकार श्री मनोज पवार की कलात्मक रंगोली को देखने के लिए शहर के कला प्रेमीयों को वर्षभर इंतजार रहता है।

इस वर्ष भी श्री मनोज पवार ने धार्मिक /सामाजिक/ प्राकृतिक विषयों को चुना है, जिनमें शहीद गुरू गोवीन्दसिंह जी (व्यक्तिचित्रण), परिवार से दुखी महिला (वेदना), छत्रपति संभाजी राजे (छावा) शेर का मुंह फाडते हुए, विश्वामित्र एवं मेनका,

बाल रूप में श्री कृष्ण जी, शिकार (बिल्ली गिलहरी को पकडे हुए), क्रोधीत व्यक्ति एवं दृश्य चित्र को कलात्मक रंगोली से चित्रित किया है।

इस बार होली के दिन दिनांक 13/03/2025 एवं 14/03/2025 को शालिनी रोड (स्वर्णकार धर्मशाला के सामने) समय सायंकाल 7.00 बजे से होने वालेइस आयोजन का आनंद लिया जा सकता है।

॥ मंदिरम् ॥ 57

शिव खोरी मंदिर, जम्मू-कश्मीर

शिव खोरी मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू गुफा मंदिर है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के रियासी शहर के पास संगर गांव, पौनी में स्थित है। श्री शिव खोरी गुफा, जिला रियासी में मंदिर के बेस कैंप रानसू से लगभग 4.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफा की खासियत 4 फुट ऊंचा प्राकृतिक रूप से बना 'भगवान शिव महाराज लिंगम' है। गुफा के अंदर पत्थरों पर प्राकृतिक देवताओं की आकृतियाँ भी अंकित हैं। ये देवता हिंदू पंथ के 33 कोटि देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। खोरी का मतलब गुफा है और शिव खोरी इस प्रकार शिव की गुफा को दर्शाता है। यह प्राकृतिक गुफा लगभग 200 मीटर लंबी, एक मीटर चौड़ी और दो से तीन मीटर ऊँची है, और इसमें एक स्वयं निर्मित शिवलिंग है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह अनंत है।

राजधानी को यह मिला बजट में

भोपाल-इंदौर मेट्रो के लिए 850 करोड़

व्यापमं समेत 3 फ्लाइओवर 139 करोड़ से बनेंगे; 300 करोड़ से 38 सड़कों का निर्माण

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल की बेहद व्यस्ततम सड़क लिंक रोड नंबर-1 के व्यापमं चौराहे पर 53 करोड़ रुपए से करीब पौन किमी लंबा नया फ्लाइओवर बनेगा। इससे वल्लभ भवन, जेल पहाड़ी आने-जाने वाले लोग बिना जाम में फंसे निकल सकेंगे। भोपाल-इंदौर स्टेट हाईवे पर फंदा के पास भी 37.70 करोड़ रुपए और सूखी सेवनिया के पास 48.58 करोड़ रुपए से दो नए फ्लाइओवर बनाए जाएंगे। बुधवार को मध्यप्रदेश के बजट में इन तीनों फ्लाइओवर को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा करीब 300 करोड़ रुपए से 38 सड़कों का निर्माण भी होगा। इनमें ज्यादा सड़कें शहर की है।

मेट्रो के लिए इतनी राशि मिली

बजट के बाद मेट्रो की ब्लू लाइन (भदभदा से रत्नागिरी तक) का काम भी शुरू हो सकेगा। भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए सरकार ने बजट में साढ़े 8 सौ करोड़ रुपए का बजट रखा है। भोपाल-इंदौर मेट्रो का काम अब अंतिम दौर में है। इनके लिए साढ़े 8 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

20 करोड़ रुपए से बनेगा स्विमिंग पुल

बाग सेवनिया स्थित राष्ट्रीय संस्कृति संस्थानम के पास ऑडिटोरियम एवं स्विमिंग पुल का निर्माण 20 करोड़ रुपए से होगा। बजट में इसे भी मंजूरी मिली है।

मनीषा मार्केट की सड़क के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई- शैतान सिंह चौराहा से मनीषा मार्केट, बंसल हॉस्पिटल, स्वर्ण जयंती पार्क, बावड़िया तिराहा से कोलार रोड तक निर्माण के लिए भू-अर्जन का कार्य 10.92 करोड़ रुपए से होगा।

विधानसभा में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने के सवाल पर सरकार का जवाब

● 19 महीनों में 35 महिलाएं लाड़ली बहना हुईं अपात्र,15748 की मौत, 3.19 लाख बहनें 60 पार के कारण बाहर ● समय-समय पर बढ़ेगी राशि

भोपाल (नप्र)। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेमचेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए किए जाने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विधानसभा में राशि बढ़ाए जाने के सवाल पर महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब दिया है कि राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

15 हजार से ज्यादा लाड़ली बहनों की मौत

विधानसभा में कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह के सवाल के जवाब में सामने आया कि जून 2023 से फरवरी 2025 तक मात्र 35 महिलाओं को लाड़ली बहना योजना से अपात्र किया गया है। जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में बताया गया कि 15748 लाड़ली बहनों की अब तक मौतें हो चुकी हैं। 60 साल की उम्र पार होने के चलते 3 लाख 19 हजार 911 महिलाएं लाड़ली बहना योजना से बाहर की गई हैं।

सितंबर 2023 से फरवरी 2025 तक 21 से 35 साल की लाडली बहनों की संख्या 59 लाख 12 हजार से घटकर 58 लाख 87 हजार हो गई है। 36 से 50 वर्ष की लाडली बहनों की संख्या 53 लाख 75 हजार से घटकर 53 लाख 43 हजार रह गई है।

हर छह महीने में होना था कार्य दक्षता मूल्यांकन

प्रताप ग्रेवाल के सवाल के उत्तर में बताया गया कि इस योजना के आदेश में उल्लेखित लाडली बहन योजना के कार्य की दक्षता मूल्यांकन की कार्यवाही प्रचलित है। जबकि योजना के आदेश के मुताबिक 6 महीने में योजना का मूल्यांकन किया जाना था। लेकिन, 18 महीने बाद भी नहीं किया गया है।

नई हितग्राही जोड़ने की फिलहाल कोई योजना नहीं- महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधानसभा में दिए जवाब में कहा यह सतत प्रकृति की योजना नहीं है। तथा लाडली बहना का हित लाभ उनका मौलिक अधिकार नहीं है। लाड़ली बहना योजना में नई हितग्राहियों को जोड़ने की कोई समय सीमा फिलहाल नहीं हैं। आदेश के नए पंजीयन के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं था। तथा वर्तमान में नवीन आवेदन प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव विचार अधीन नहीं है। लाड़ली बहना की राशि न बढ़ाए जाने के सवाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि योजना में न कोई कटौती की जाएगी न योजना बंद की जाएगी। कोई भी योजना पूरे कार्यकाल के लिए होती है। संकल्प पत्र पूरे पांच साल के लिए होता है।

डीजीपी के त्योहार को लेकर निर्देश

संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी

सोशल मीडिया पर भी रहेगी कड़ी नजर

भोपाल (नप्र)। रमजान और आगामी होली, रंगपंचमी के दौरान प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा ने पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सभी एडीजी, आईजी, पुलिस आयुक्त (भोपाल-इंदौर), रेंज डीआईजी और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।

सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मनाए जाएं त्यौहार- डीजीपी कैलाश मकवाणा ने निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी त्यौहार शांतिपूर्वक और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाए जाएं। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए और ग्राम रक्षा समिति व स्थानीय नागरिकों का सहयोग लिया जाए। इसके अलावा, शांति समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए।

महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान- डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की अभद्रता और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाए और महिला सुरक्षा के लिए गश्त (पेट्रोलिंग) बढ़ाई जाए।

अवैध गतिविधियों पर सख्ती- होली और रंगपंचमी के दौरान अवैध शराब विक्रेताओं और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने कहा कि डीजे पर आपत्तिजनक गाने न बजाए जाएं और इसके लिए डीजे संचालकों को पहले ही निर्देशित किया जाए।

संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी- पिछले वर्षों में जहां भी सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई हैं, उन स्थानों को चिह्नित कर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी करने, पुलिस गश्त बढ़ाने और शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग- डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए।

छात्रवृत्ति की भीख मांगने निकले एनएसयूआई कार्यकर्ता

भोपाल में कटोरा लेकर प्रदर्शन; विधानसभा जाने से पहले पुलिस ने रोका

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में नर्सिंग छात्रों की छात्रवृत्ति और परीक्षा में हो रही देरी के खिलाफ बुधवार को एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। पदाधिकारी-कार्यकर्ता हाथों में कटोरा लेकर विधानसभा की ओर निकले। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इससे नाराज वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार के नेतृत्व में हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया गया। नर्सिंग छात्र-छात्राएं अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक कटोरा लेकर पैदल मार्च करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने रेडक्रॉस अस्पताल के पास बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके विरोध में छात्र-छात्राओं ने वहीं सड़क पर बैठकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया।

जयवर्धन सिंह ने नर्सिंग छात्रों को दिया समर्थन- पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और नर्सिंग छात्रों की समस्याएं सुनीं। छात्रों ने उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। जिस पर उन्होंने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग

की। सिंह ने कहा कि कांग्रेस नर्सिंग छात्रों के हक की इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ खड़ी है। सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों को हम सदन से सड़क तक उजागर करेंगे।

नर्सिंग शिक्षा की बदहाल स्थिति

विधायक सिंह ने कहा कि प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। 2019-20 सत्र के बीएससी नर्सिंग छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं हो पाना 2020-21 और 2021-22 सत्र के बीएससी, एमएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग छात्रों की सेकेंड ईयर की परीक्षाएं लंबित हैं।

उज्जैन में नायब तहसीलदार की रीडर 5000 रुपये की घूस लेते गिरफ्तार

महिदपुर/उज्जैन (नप्र)। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार की रीडर को 5000 रुपये की घूस लेते गिरफ्तार किया है। महिला कर्मचारी ने पट्टे की जमीन में नाम की त्रुटि सुधारने के लिए 10 हजार रुपये मांगे थे। शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है।

लोकायुक्त डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल ने बताया कि हाकम चौहान पुत्र भेरूलाल निवासी मादुपुरा खेड़ा खजूरिया ने तहसील कार्यालय में पट्टे की जमीन के नाम में त्रुटि में बदलाव करवाने के लिए आवेदन दिया था। इसके एवज में तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार की रीडर दीपा चेलानी द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। बुधवार को दीपा को प्रथम किश्त में 5000 रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। केस दर्ज जांच की जा रही है।

भूपेंद्र सिंह बोले- हेमंत कटारे फर्जी उपनेता प्रतिपक्ष

बाला बच्चन गृहमंत्री थे तो डॉग के तबादले होते थे; करोड़पति कॉन्स्टेबल का मामला भी उठा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज,नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मिलने विधानसभा पहुंचे

भोपाल (नप्र)। बुधवार को लंच के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश-प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पीछे जा रही है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का अपमान करती है।

इस पर कांग्रेस विधायकों ने बयान का विरोध करते हुए इसे कार्यवाही से विलोपित करने के लिए कहा। हंगामे की स्थिति बनने पर स्पीकर ने कहा कि अगर कोई बात आपत्तिजनक है, तो उसे विलोपित कर दिया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस पार्टी के अध्यक्ष ये कहें कि कुंभ में नहाने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगी, तो यह सोचने वाली बात है। इसके बाद बाला बच्चन ने कहा कि कुंभ नहाने मैं भी परिवार के साथ गया था, लेकिन यह अभिभाषण का विषय नहीं है। इसके बाद अध्यक्ष ने व्यवस्था दी सभी सदस्य अभिभाषण के विषय पर ही बोलेंगे। भूपेंद्र सिंह ने बाला बच्चन पर तंज कसते हुए कहा कि जब यह गृह मंत्री थे तो इनके समय डॉग के तबादले होते थे। मैं भी गृहमंत्री था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होती थी। सदन में करोड़पति कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा का मामला भी उठा।

वहीं, भूपेंद्र सिंह ने उपनेता प्रतिपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हेमंत कटारे की पत्नी, और उनकी मां पर ईओडब्ल्यू में भी केस दर्ज है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान नहीं है, फिर यह फर्जी उपनेता प्रतिपक्ष बनकर घूम रहे हैं।

विधानसभा में अभिभाषण पर चर्चा पर हुई नोंकझोंक

- बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा- कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का अपमान करती है।

- विजयवर्गीय ने कहा- जिस पार्टी के अध्यक्ष ये कहें कि कुंभ में नहाने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगी, तो यह सोचने वाली बात है।
- भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक बाला बच्चन को लेकर कहा कि जब यह गृह मंत्री थे तो उनके समय डॉग के तबादले होते थे।
- भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे को फर्जी उपनेता प्रतिपक्ष बताया। उन्होंने कहा-विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान नहीं है।
- हेमंत कटारे को बलात्कारी और चोर कहते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इनके खिलाफ धोखाधड़ी का भी केस दर्ज है।

संस्कृति बचाओ मंच के प्रमुख चंद्रशेखर तिवारी पर एफआईआर

भोपाल में प्रदर्शन के दौरान टूटा था कांग्रेस का मंच; पुलिस ने जांच के बाद की कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। भोपाल में सोमवार को किसान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शन के दौरान रंगमहल चौराहा पर बना मंच अचानक टूट गया। जिससे 10 से ज्यादा कांग्रेसी घायल हो गए। इस घटना के बाद टीटी नगर पुलिस ने जांच के बाद हिंदूवादी नेता और संस्कृति बचाओ मंच के प्रमुख चंद्रशेखर तिवारी पर एफआईआर दर्ज की है। चंद्रशेखर तिवारी पर आरोप है कि कार्यक्रम के लिए जो मंच तैयार किया गया था, वह उन्हीं ने बनवाया था। मंच निर्माण के लिए उनके टेंट हाउस से पूरा सामान आया था। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मंच को जानबूझकर कमजोर बनाया गया, ताकि यह गिर जाए और हादसा हो। मंच टूटने की घटना को कांग्रेस ने आपराधिक षड्यंत्र बताया और चंद्रशेखर तिवारी पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत कार्रवाई की मांग की।

मना किया था, धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा- करवा दीजिए- संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोपों का खंडन किया है। कहा- किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने 9 मार्च की शाम 7:00 बजे कहा कि मेरा यह कार्यक्रम आप करवा दीजिए। मैने उन्हें मना किया। इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से आप यह काम करा दीजिए। मेरा यह पहला प्रदर्शन है।